



3 गोवंश तस्करी प्रयास विफल, 18 गोवंशों को मुक्त करवाया

5 ऋषभ पंत ने तोड़ा सहवाग का रिकार्ड, टेस्ट क्रिकेट में लगाए सबसे ज्यादा छक्के

8 आधुनिक कृषि प्रणाली

न्यूतम 11

मौसम जम्मू 21



E-mail: dehatsandesh@gmail.com

जम्मू-कश्मीर का एकमात्र ग्रामीण दैनिक

देहात सन्देश



वर्ष-22, जम्मू तवी, अंक-281

जम्मू तवी, रविवार 16 नवम्बर, 2025

मूल्य-3 रुपये- (लेह)4 रुपये

पृष्ठ -8

नौगाम पुलिस स्टेशन में 'आकस्मिक' विस्फोट में 9 लोगों की मौत, डीजीपी ने आतंकी पहलू से किया इनकार

श्रीनगर, 15 नवंबर । जम्मू-कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए भीषण विस्फोट में मारे गए नौ लोगों में राज्य जॉब एजेंसी के इंस्पेक्टर इसरार अहमद शाह भी शामिल थे। इसरार अहमद शाह 2011 में पुलिस बल में शामिल हुए थे के परिवार में पत्नी, दो छोटे बच्चे और बुजुर्ग माता-पिता हैं। कुपवाड़ा जिले के द्रुमुल्ला इलाके के रहने वाले शाह एक मुदुभाषी व्यक्ति थे और अपने काम पर ज्यादा ध्यान देते थे, ऐसा उनके पिछले गुलाम मोहम्मद ने बताया। पुलिस अधिकारी की एक मददगार व्यक्ति के रूप में भी प्रतिष्ठा थे, जो उनके निधन की खबर गौं में पहुँचते ही उनके घर पर उमड़ पड़सियों की भीड़ से स्पष्ट था। मृतकों में चयन श्रेणी कांस्टेबल जावेद मंसूर राथर और अशीद अहमद शाह (दोनों क्राइम ब्रांच के फोटोग्राफर), चयन श्रेणी कांस्टेबल

उपराज्यपाल सिन्हा ने नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए विस्फोट में मारे गए नौ लोगों को दी श्रद्धांजलि

श्रीनगर, 15 नवंबर । जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शनिवार को नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए आकस्मिक विस्फोट में मारे गए नौ लोगों को पुष्पांजलि अर्पित की। इस विस्फोट में 32 लोग घायल भी हुए हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सिन्हा ने पुलिस नियंत्रण कक्ष में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अधिकारियों ने बताया कि जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव अटल डुल्लू, एनआईए के महानिदेशक सदानंद दाते, डीजीपी नलिन प्रभात, सेना की 15वीं कोर के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत श्रीवास्तव और नागरिक प्रशासन, पुलिस तथा अन्य सुरक्षा बलों और एजेंसियों के अन्य अधिकारियों ने भी शहीद पुलिसकर्मियों को पुष्पांजलि अर्पित की। मृतकों में छह पुलिसकर्मियों शामिल हैं - राज्य जॉब एजेंसी के इंस्पेक्टर इसरार अहमद शाह, चयन ग्रेड कांस्टेबल जावेद मंसूर राथर और अशीद अहमद शाह (दोनों अपराध शाखा के फोटोग्राफर), चयन ग्रेड कांस्टेबल एजाज अफजल मीर और कांस्टेबल मोहम्मद अमीन मीर और शौकत अहमद भट (तीनों फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में कार्यरत)। नायब तहसीलदार मुजफ्फर अहमद खान, इलाके के चौकीदार सुहेल अहमद राथर और दर्जी मोहम्मद शाफी पारं भी इस आकस्मिक विस्फोट में मारे गए। पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात ने बताया कि विस्फोट इस समय हुआ जब अधिकारियों की एक टीम सफेदपोश आतंकी मॉड्यूल मामले की जाँच के दौरान जवाब दिए गए विस्फोटकों के

सरकार आदिवासी समाज को राष्ट्र के सर्वोच्च पदों तक पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध : प्रधानमंत्री

नर्मदा, 15 नवंबर । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को जोर देकर कहा कि राजनीतिक सशक्तिकरण के बिना विकास अधूरा है और इसी उद्देश्य से केंद्र सरकार आदिवासी समाज को राष्ट्र के सर्वोच्च पदों तक पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि किसी भी समाज या समुदाय के संपूर्ण विकास के लिए राजनीतिक नेतृत्व और लोकतंत्र में उसकी समान भागीदारी अत्यंत आवश्यक होती है। प्रधानमंत्री गुजरात के नर्मदा जिले के डेडियापाड़ा में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर आयोजित जनजातीय गौरव दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस अवसर पर लगभग 9,700 करोड़ रुपये की सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी और कनेक्टिविटी से संबंधित परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि यह निवेश आदिवासी क्षेत्रों की जीवन गुणवत्ता में बड़ा बदलाव लाएगा। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज ने भारतीय सभ्यता, संस्कृति और स्वतंत्रता संग्राम में जो योगदान दिया है, वह अतुलनीय है, लेकिन दशकों तक इस योगदान को नजरअंदाज किया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने आदिवासी समाज के सम्मान, स्वाभिमान और विकास को प्राथमिकता देकर इस ऐतिहासिक उपेक्षा को दूर करने का काम किया है। उन्होंने कहा, आज देश की राष्ट्रपति एक आदिवासी महिला हैं। यह केवल सम्मान नहीं, बल्कि वह प्रेरणा है जो बताती है कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था हर नागरिक को उच्चतम पद तक पहुँचाने का अवसर देती है। मोदी ने कहा कि



“ प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व केवल प्रतीकात्मक नहीं होना चाहिए, बल्कि वास्तविक शक्ति-हस्तांतरण का माध्यम होना चाहिए

भाजपा और राजग सरकारों ने हमेशा सक्षम, प्रतिभाशाली और जनसेवा के प्रति समर्पित आदिवासी नेताओं को आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, नगालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो, मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगुभाई पटेल, सभी उस परिवर्तनशील राजनीतिक यात्रा के प्रतीक हैं जिसमें आदिवासी समाज नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि केंद्र में सर्वानंद सोनोवाल, जो आदिवासी समुदाय से आते हैं, पूरे शिपिंग मंत्रालय का नेतृत्व कर रहे हैं।

खबर संक्षेप

तलाशी अभियान के दौरान एक आईईडी बरामद, सुरक्षित रूप से किया नष्ट

राजीरी, 15 नवंबर । सुरक्षाबलों ने शनिवार को जम्मू-कश्मीर के राजरी जिले के थानमंडी इलाके में तलाशी अभियान के दौरान एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) बरामद किया। अधिकारियों ने बताया कि नियमित जाँच के दौरान इस उपकरण का पता चला जिसके बाद बम निरोधक दल को बुलाया गया। विशेषज्ञों ने आईईडी को मौके पर ही सुरक्षित रूप से नष्ट कर दिया। उन्होंने बताया कि किसी और विस्फोटक उपकरण की मौजूदगी की संभावना से इनकार करने के लिए इलाके में तलाशी अभियान जारी है।

सांबा में नाले की खुदाई के दौरान मिला जंग लगा मोटार का एक गोला

जम्मू, 15 नवंबर । जम्मू-कश्मीर के सांबा जिले में शनिवार को एक नाले की खुदाई के दौरान जंग लगा मोटार का एक गोला मिला। अधिकारियों ने बताया कि यह गोला सुबह 10 बजे करबे के एक शैक्षणिक संस्थान के पास कुछ मजदूरों ने देखा। अधिकारियों के अनुसार सूचना मिलते ही संबंधित पुलिस थाने की एक टीम मौके पर पहुँची और इलाके को सील कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया है और उच्च श्रेणी के विस्फोटक पदार्थ को निष्क्रिय करने के प्रयास जारी हैं।

घाटी के अधिकतम जिलों में न्यूनतम तापमान में और गिरावट दर्ज, श्रीनगर में बीती रात रही इस मौसम की सबसे ठंडी रात

श्रीनगर, 15 नवंबर । कश्मीर घाटी के अधिकतम जिलों में न्यूनतम तापमान में और गिरावट आई है। जम्मू-कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में इस मौसम की सबसे ठंडी रात दर्ज की गई जहाँ तापमान शून्य से नीचे 2.4 डिग्री सेल्सियस रहा। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पहलगाम में न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे 3.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कश्मीर के प्रवेश द्वार काजीगुंड में न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे 2.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि कुपवाड़ा में पारा शून्य से नीचे 2.4 डिग्री सेल्सियस रहा। विवरण के अनुसार प्रसिद्ध स्की रिसॉर्ट गुलमार्ग में न्यूनतम तापमान 0.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। हालांकि कोकरनाग में रात का तापमान 1.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

सांबा में जंग लगा मोटार का खोल मिला; निष्क्रिय करने के प्रयास जारी

जम्मू, 15 नवंबर । जम्मू-कश्मीर के सांबा जिले में शनिवार को एक नाले की खुदाई के दौरान जंग लगा मोटार का खोल मिला, अधिकारियों ने बताया कि यह खोल सुबह 10 बजे करबे के एक शैक्षणिक संस्थान के पास कुछ मजदूरों ने देखा। अधिकारियों के अनुसार, सूचना मिलते ही संबंधित पुलिस थाने की एक टीम मौके पर पहुँची और इलाके को सील कर दिया। बम निरोधक दस्ते की एक टीम को बुलाया गया है और उच्च श्रेणी के विस्फोटक पदार्थ को निष्क्रिय करने के प्रयास जारी हैं।

आकस्मिक विस्फोट से आस-पास की इमारतों को हुए नुकसान की भरपाई करेगी सरकार : मुख्यमंत्री

श्रीनगर, 15 नवंबर । जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शनिवार को कहा कि सरकार नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए आकस्मिक विस्फोट से आस-पास की इमारतों को हुए नुकसान की भरपाई करेगी। अब्दुल्ला ने कहा कि सरकार पीड़ित परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि सरकार नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए दुःखद विस्फोट में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री सकीना इट्ट को घायलों के सर्वोत्तम उपचार सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है और आश्वासन दिया है कि क्षतिग्रस्त इमारतों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। शुक्रवार देर रात एक भीषण विस्फोट हुआ जब अधिकारी सफेदपोश आतंकी मॉड्यूल मामले में जब्त किए गए विस्फोटकों के एक बड़े जखीरे से नमूने निकाल रहे थे और श्रीनगर के बाहरी इलाके में नौगाम पुलिस



स्टेशन परिसर में संग्रहीत थे। विस्फोट में नौ लोग मारे गए और 32 अन्य घायल हो गए जिससे पुलिस स्टेशन की इमारत बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और आस-पास की इमारतें भी प्रभावित हुईं। जम्मू-कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए भीषण विस्फोट में मारे गए नौ लोगों में राज्य जॉब एजेंसी के इंस्पेक्टर इसरार अहमद शाह भी शामिल थे। शाह, जो 2011 में पुलिस बल में शामिल हुए थे, के परिवार में पत्नी, दो छोटे बच्चे और बुजुर्ग माता-पिता हैं।

उपराज्यपाल ने श्रीनगर में उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की

श्रीनगर, 15 नवंबर । जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए आकस्मिक विस्फोट के बाद शनिवार को पुलिस और नागरिक प्रशासन के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस विस्फोट में नौ लोगों की मौत हो गई और 32 घायल हुए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। राजभवन में आयोजित बैठक में सिन्हा को कश्मीर में आतंकी तंत्र को नष्ट करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि बैठक में जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव अटल डुल्लू, गुह सचिव चंद्राकर भारती, पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात, विशेष पुलिस महानिदेशक एस जे एम गिलानी, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सीआईडी नीतीश कुमार सहित अन्य अधिकारी शामिल हुए।

सिन्हा ने जानकारी के नुकसान पर गहरा दुःख व्यक्त किया है और विस्फोट के सही कारणों का पता लगाने के लिए जाँच के आदेश दिए हैं। यह विस्फोट शुक्रवार रात करीब 11-20 बजे हुआ जब एक विशेष टीम एक सफेदपोश आतंकी मॉड्यूल की जल रही जाँच के सिलसिले में जब्त किए गए विस्फोटकों के एक बड़े और अस्थिर जखीरे से नमूने निकाल रही थी। विस्फोटकों का एक बड़ा हिस्सा नौगाम पुलिस स्टेशन के एक खुले क्षेत्र में सुरक्षित रूप से रखा गया था। जम्मू-कश्मीर पुलिस के महानिदेशक नलिन प्रभात और गुह मंत्रालय के संयुक्त सचिव (कश्मीर) प्रशांत लोखंडे ने बताया कि यह घटना उस समय हुई जब अधिकारी हरियाणा के फरीदाबाद में जैश-ए-मोहम्मद के सफेदपोश आतंकी मॉड्यूल मामले में जब्त किए गए विस्फोटकों के बड़े जखीरे से नमूने की जाँच कर रहे थे।

देश के हर मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल में अमृत फार्मेसी स्थापित की जाएगी : जेपी नड्डा

नई दिल्ली, 15 नवंबर । केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने शनिवार को देशभर में अमृत नेटवर्क के व्यापक विस्तार की घोषणा करते हुए कहा कि अब लक्ष्य है कि देश के हर मेडिकल कॉलेज और हर जिला अस्पताल में अमृत फार्मेसी उपलब्ध कराई जाए, ताकि सस्ती दवाओं की पहुँच हर नागरिक तक सुनिश्चित हो सके।

नड्डा यहां भारत मंडप में अमृत (उपचार के लिए फिकायती दवाएं और विश्वसनीय प्रत्यारोपण) फार्मेसी के 10वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन करने के बाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। नड्डा ने कहा कि वर्ष 2014 में मोदी सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ, सस्ती और सर्वसुलभ बनाने का संकल्प लिया था। इसी दृष्टि से जन औषधि और अमृत जैसी योजनाओं की परिकल्पना की गई, जिनका उद्देश्य नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण दवाएं रियायती दरों पर उपलब्ध कराना है।

उन्होंने बताया कि 2015 में शुरू हुए अमृत फार्मेसी कार्यक्रम ने आज एक दशक में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। वर्तमान में देशभर में 255 अमृत आउटलेट कार्यरत हैं और निरंतर भविष्य में इन्हें बढ़ाकर 500 तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। यह नेटवर्क न केवल बढ़ रहा है बल्कि ज्यादा कुशल और मजबूत भी हो रहा है। नड्डा ने कहा कि अमृत फार्मेसी द्वारा 50 से 90 प्रतिशत तक की छूट पर दवाएं और इम्प्लांट उपलब्ध कराना बड़ी उपलब्धि है। अब तक 6.85 करोड़ से अधिक मरीज अमृत की सेवाओं से लाभान्वित हुए हैं। इसके अतिरिक्त 17 हजार

करोड़ रुपये से अधिक की एमआरपी कीमत वाली दवाएं छूट पर प्रदान की गईं, जिससे मरीजों को कुल मिलाकर 8,500 करोड़ रुपये से अधिक की बचत हुई है। अमृत फार्मेसी के बारे में जन-जागरूकता बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है, ताकि अधिक से अधिक नागरिक इस सुविधा का लाभ उठा सकें। समारोह में नड्डा ने कहा, फ्रंटम सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अमृत फार्मेसी नेटवर्क इसका सशक्त माध्यम है। एचएलएल पिछले 60 वर्षों से उच्छेद सेवाएं दे रहा है और नया ईको-ग्रीन सिस्टम पूरी सप्लाय चेन को और अधिक स्मार्ट, तेज और कुशल बनाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुष्प सिलता श्रीवास्तव ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के विजन और स्वास्थ्य मंत्री नड्डा के मार्गदर्शन में अमृत पहल की शुरुआत हुई थी, जिसका उद्देश्य था- हर नागरिक के लिए गुणवत्तापूर्ण दवाओं की सस्ती और समान पहुँच सुनिश्चित करना।

रुहुल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रति जवाबदेह हैं, वह हल की बदौलत सांसद हैं : फारुक

श्रीनगर, 15 नवंबर । नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के अध्यक्ष डॉ. फारुक अब्दुल्ला ने शनिवार को कहा कि श्रीनगर संसदीय क्षेत्र से सांसद आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी अपने किए के लिए पार्टी के प्रति जवाबदेह हैं। समाचार एजेंसी के अनुसार, अब्दुल्ला ने यहां प्रचारकों से बात करते हुए कहा, रुहुल्लाह हल (एनसी) की बदौलत सांसद हैं। उन्हें इस हल से प्यार करना चाहिए और इसे मजबूत करना चाहिए। हमारे कार्यकर्ताओं ने अच्छा काम किया है, हमें अच्छी संख्या में वोट मिले हैं, लेकिन हार-जीत तो जीवन का हिस्सा है। बड़गाम विधानसभा उपचुनाव में पार्टी की हार पर प्रतिक्रिया देते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि इस नतीजे को एक झटके के बजाय एक सबक के रूप में लिया जाना चाहिए और पार्टी अपनी कमियों पर

बड़गाम की हार को सबक बताते हुए फारुक अब्दुल्ला ने कहा, आत्मचिंतन की जरूरत

हराया। लंबे समय से नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ मानी जाने वाली बड़गाम सीट, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा गंदेबल सीट बरकरार रखने के लिए इस सीट को छोड़ने के बाद हुए उपचुनाव में पार्टी के हाथ से निकल गई। इस बीच, नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए भीषण विस्फोट के बारे में बोलते हुए, अब्दुल्ला ने कहा यह हमारी गलती है; जो लोग इस विस्फोट को बेहतर समझते हैं, उन्हें पहले इस बारे में सलाह लेनी चाहिए थी कि इससे कैसे निपटा जाए, बजाय इसके कि हम खुद इससे निपटने की कोशिश करें।

सीसीआई अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर लंबित मुद्दों को प्राथमिकता देने का आग्रह किया

जम्मू, 15 नवंबर । चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (सीसीआई) के अध्यक्ष अरुण गुप्ता ने शनिवार को जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात कर विकास और व्यावसायिक मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। शुरुआत में, गुप्ता ने इस मुद्दे को सुलझाने और वार्षिक दरबार मूल को फिर से शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह निर्णय न केवल सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने में मदद करेगा, बल्कि दोनों क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को भी काफी बढ़ावा देगा। हालांकि, गुप्ता ने मुख्यमंत्री को बताया कि बार-बार चर्चा के बावजूद, कई महत्वपूर्ण मुद्दे और मांगें अभी भी लंबित हैं और सरकार को तत्काल ध्यान देने की

मुख्य सचिव ने केंद्र शासित प्रदेश में युवा सहभागिता एवं सशक्तिकरण कार्यक्रम की योजनाओं और तैयारियों का मूल्यांकन किया

जम्मू, 15 नवंबर । मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने शनिवार को आगामी युवा सहभागिता एवं सशक्तिकरण कार्यक्रम की विभागीय तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। यह कार्यक्रम केंद्र शासित प्रदेश में एक पहल है जिसका उद्देश्य जम्मू और कश्मीर के सभी जिलों में सांस्कृतिक, शैक्षणिक, उद्यमशीलता और समुदाय-उन्मुख गतिविधियों में युवाओं की सार्थक भागीदारी को बढ़ावा देना है। बैठक में कई वरिष्ठ प्रशासनिक प्रमुखों ने भाग लिया, जिनमें कृषि उत्पादन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव; संस्कृति और चर्ची हिम्मत में भूखंडों के विभाजन का मुद्दा उठाया गया, साथ ही जम्मू में नई आवासीय कॉलोनिजों और वाणिज्यिक बाजारों के विकास की मांग भी की गई।



विभागों के आयुक्त सचिव; जम्मू और कश्मीर के संभागीय आयुक्त; आईटी सचिव; कौशल विकास विभाग के सचिव; आर्थिक एवं सांख्यिकी महानिदेशक; युवा सेवा एवं खेल महानिदेशक; एनआईसी के उप महानिदेशक; कॉलेज निदेशक; और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। सभी जिलों के उपायुक्तों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया। बैठक के दौरान, मुख्य सचिव ने प्रत्येक विभाग से उनके प्रस्तावित गतिविधि कैलेंडर और मेगा युवा जुड़ाव अभियान की रणनीतियों पर



लॉ में किया है ग्रेजुएशन तो इन क्षेत्रों में बना सकते हैं करियर

करियर के रूप में लॉ देश में विस्तृत रूप से फैला हुआ एक प्रेफेशन है जो सोसाइटी के लिए कार्य करता है। लॉ प्रोफेशनल विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सामंजस्य का कार्य करता है। लॉ की पढ़ाई करने के बाद युवाओं के लिए करियर के कई रास्ते खुल जाते हैं जिसकी मदद से रिकल्स का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है। केवल करियर ही नहीं बल्कि इस प्रोफेशन में सम्मान भी बहुत मिलता है। अगर आप भी लॉ की पढ़ाई करने का विचार कर रहे हैं तो जान लें कि क्षेत्रों में आप करियर बना सकते हैं।

क्रिमिनल लॉयर

आपराधिक मामलों के लिए अदालत में अपने मुक्किलों का प्रतिनिधित्व क्रिमिनल लॉयर ही करता है। वे स्थानीय अदालत, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में अपने मुक्किल के लिए अदालत में मामले पेश करते हैं। भारत में एक क्रिमिनल लॉयर को औसतन 7 लाख प्रतिवर्ष सैलरी मिलती है। जहां फेशर को प्रतिवर्ष औसतन 2 लाख रुपये और अनुभवी लॉयर को प्रतिवर्ष औसतन 30 लाख रुपये तक सैलरी तक मिल सकती है।

कॉरपोरेट लॉयर

कॉरपोरेट लॉयर कंपनियों को उनके इंडस्ट्री के नियमों का पालन करने में मदद करते हैं। वे कंपनी के गठन और

मेनेजमेंट से संबंधित सभी कानूनी प्रक्रियाओं में अपने क्लाइंट की सहायता करने के लिए जिम्मेदार हैं। कॉर्पोरेट लॉयर को प्रतिवर्ष औसतन 6.9 लाख रुपये मिलते हैं।

ज्यूडिशियल सर्विस

लॉ करने के बाद सरकारी नौकरी के भी उतने ही अवसर हैं। अगर आपने लॉ में ग्रेजुएशन किया है और आप सरकारी नौकरी में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए ज्यूडिशियल सर्विस के रास्ते खुले हैं। इसके लिए आपको राज्यों द्वारा आयोजित होने वाले प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होना होगा। परीक्षा में चयनित होने के बाद 2.2 लाख प्रतिमाह सैलरी दी जाएगी और साथ ही अन्य सुविधाएं भी दिए जाएंगे।

लीगल पत्रकार

अगर आप लीगल मुद्दों पर लिखने का शौक रखते हैं और पत्रकारिता को करियर के रूप में चुनना चाहते हैं तो आपके लिए लीगल पत्रकार के रूप में करियर का बेहतर ऑप्शन मौजूद है। इस क्षेत्र में करियर के लिए आपके पास बेहतर कम्युनिकेशन और राइटिंग रिकल्स होनी चाहिए। बेहतर अवसरों के साथ यह करियर का बेहतर और बेहद अलग ऑप्शन हो सकता है। एक लीगल पत्रकार भारत में प्रतिवर्ष 3.7 लाख रुपये की सैलरी के शुरुआत कर सकते हैं।



इंटीरियर डिजाइनिंग उन युवाओं के लिए बेहतरीन करियर ऑप्शन है, जो कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं। इंटीरियर डिजाइनिंग उन युवाओं के लिए बेहतरीन करियर ऑप्शन है, जो कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं।

सी

मित स्थान में घर, दफ्तर, मॉल या किसी भी प्रॉपर्टी के लिए ऐसा डिजाइन तैयार करना, जिससे वह सुंदर और व्यवस्थित दिखे, यह काम इंटीरियर डिजाइनर का होता है। इंटीरियर डिजाइनिंग एक विज्ञान है, जिसमें आपको जगह के बारे में अच्छी जानकारी होना जरूरी है, ताकि छोटे-से-छोटे एरिया को आकर्षक बनाया जा सके। आज छोटे शहरों और गांवों से लोग बड़े शहरों का रुख कर रहे हैं और कम जगह में ज्यादा लोगों को घर देने के लिए जो प्लेट कल्चर पैदा हुआ है, उसने भी इंटीरियर डिजाइनर की भूमिका बहुत खास बना दी है। छोटे-छोटे घरों में पूरे परिवार के हिसाब से सामान व्यवस्थित करना, ताकि कम जगह में भी घर खूबसूरत लगे, यह काम इंटीरियर डिजाइनर ही कर सकता है। वैसे तो इंटीरियर डिजाइनिंग अपने आप में स्पेशलाइजेशन वाला कोर्स है, लेकिन इसके अंतर्गत ऑफिस डिजाइनिंग, किचन डिजाइनिंग, रूम्स डिजाइनिंग, बिजनेस डिजाइनिंग और होम डेकोर में एक्सपर्टीज हासिल कर सकते हैं। इंटीरियर डिजाइनर का काम काफी चुनौतीपूर्ण होता है। प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए पूरी टीम से सहयोग बिठाना होता है। साथ ही, कस्टमर के बजट और पसंद के मुताबिक घर को सजाना होता है। कई बार जो डिजाइन तैयार किया जाता है, वह ग्राहक को पसंद नहीं आता या वह उसमें कुछ बदलाव चाहता है। इसलिए बीच-बीच में उसको अपना काम दिखाते रहना होता है। इंटीरियर डिजाइनर की भूमिका इसलिए भी अहम होती है कि वह अपनी ट्रेनिंग, क्रिएटिविटी और अनुभव के आधार पर ऐसे काम करता है, जिससे किसी भी स्पेस का सही और सुंदर रूप सामने आता है। वहीं तय करता है कि किसी भी घर को आकर्षक बनाने में किस तरह के रंगों का चयन किया जाए, सोफा, टेबल, डाइनिंग टेबल, बेड समेत पूरे फर्नीचर का लुक और डिजाइन कैसा हो। फैंसी लाइट्स

बेहतरीन करियर ऑप्शन है इंटीरियर डिजाइनिंग

और डेकोरेटिव सामान से घर को सजाना भी इंटीरियर डिजाइनर के जिम्मे होता है।

कहां-कहां मौके

अपना घर सजाना किसे अच्छा नहीं लगता? खासकर सेलिब्रिटी और हाई प्रोफाइल लोगों के बीच तो इंटीरियर डिजाइनर से अपने बंगले को खूबसूरत बनवाने का खूब चलन है। इंटीरियर

क्वॉलिफिकेशन

और कोर्स

इंटीरियर डिजाइनिंग में आप बारहवीं के बाद डिप्लोमा, डिग्री और सर्टिफिकेट कोर्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के बाद भी इस क्षेत्र में आना चाहें, तो पीजी डिप्लोमा, डिग्री कोर्स कर सकते हैं। आप इस फील्ड में बैचलर इन इंटीरियर डिजाइन, बीए इन इंटीरियर आर्टिटेक्चर एंड डिजाइन, डिप्लोमा इन इंटीरियर स्पेस एंड फर्नीचर डिजाइन, पीजी डिप्लोमा इन इंटीरियर डिजाइन जैसे कोर्स कर सकते हैं।

सैलरी

इंटीरियर डिजाइनर के रूप में शुरुआत में 15 से 20 हजार रुपये महीना तक सैलरी मिल जाती है। शुरुआत में किसी फर्म में नौकरी करना उचित रहता है क्योंकि इससे काम करने का तरीका पता चलता है और प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ-साथ अनुभव भी बढ़ता है।

फोटोग्राफी के लिए इनोवेटिव होना जरूरी है ताकि किसी विजुअल को अलग ढंग से देख सकें और उसका महत्व समझ सकें। तस्वीरें खींचने का अपना मजा है लेकिन एक सफल फोटोग्राफर बनने के लिए पैशन भी चाहिए। आपके अंदर तस्वीरों के जरिये कहानी बयान करने की चाहत होनी चाहिए। सही पल को कैमरे में कैद करने की कला आएगी, तभी इस फील्ड में काम के साथ कमाई हो पाएगी। फोटोग्राफी एक टेक्निकल लाइन भी है। ऐसे में खुद को अपडेट रखना और कैमरे की टेक्नोलॉजी से परिचित रहना जरूरी है। जिन युवाओं का मन नौ से पांच की नौकरी करने के बजाय कैमरे से देश-दुनिया को एक्सप्लोर करने का करता है, उनके लिए यह एक परफेक्ट फील्ड हो सकता है।

जॉब का स्कोप

फोटोग्राफी में ट्रेनिंग लेने के बाद प्रेस फोटोग्राफर, फैशन फोटोग्राफर, पोर्ट्रेट फोटोग्राफर, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, फीचर फोटोग्राफर, फोरेंसिक फोटोग्राफर, साइटिफिक फोटोग्राफर बन सकते हैं और प्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। यह एक ऐसा फील्ड है, जहां आपको अंतरराष्ट्रीय एक्सपोजर भी मिल सकता है। हर कंपनी अपने प्रोडक्ट के साथ कैलेंडर, मेगजीन, विज्ञापन ब्रोशर आदि प्रकाशित करती हैं, जिनमें आकर्षक और स्टाइलिश तस्वीर के लिए फोटोग्राफर की खास भूमिका होती है। मीडिया, ट्रेवल, फिल्म और फैशन इंडस्ट्री बूम करने से यहां फोटोग्राफी का भविष्य काफी उज्ज्वल है। रेगुलर जॉब में आप 15 से 20 हजार रुपये प्रति माह कमा सकते हैं। बाद में प्रोफाइल के मुताबिक सैलरी बढ़ती जाती है।

कोर्स व

क्वॉलिफिकेशन

फोटोग्राफी में बारहवीं और ग्रेजुएशन के बाद सर्टिफिकेट, डिप्लोमा कोर्स और डिग्री ले सकते हैं। मीडिया के सब्जेक्ट में भी कैमरा पढ़ाया जाता है, जिसके बाद कैमरे की एडवांस ट्रेनिंग और पढ़ाई की जा सकती है।



टेक्सटाइल इंडस्ट्री में करियर बनाना आसान

सभी देश के विकास में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान है। भारत में भी इस इंडस्ट्री का देश की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका है। इसे देश के सबसे पुराने इंडस्ट्री में से एक माना जाता है। टेक्सटाइल डिजाइनिंग व इंजीनियरिंग के सुनहरे भविष्य के मद्देनजर अगर इसे दुनिया की एक बड़ी उभरती हुई इंडस्ट्री कहा जाए, तो गलत नहीं होगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए सरकार की संशोधित टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्क्रीम से टेक्सटाइल सेक्टर में करीब 1 लाख करोड़ रुपये का निवेश होने और 30 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। भारत में यह इंडस्ट्री रिसर्च, डेवलपमेंट, मेन्युफैक्चरिंग और मर्केटाइजिंग जैसी कई श्रेणियों में काम कर रही है। जिसके कारण इसमें जॉब के अवसर भी पहले की अपेक्षा अब तेजी से बढ़ रहे हैं।

टेक्सटाइल इंजीनियरिंग क्या है

अगर टेक्सटाइल सेक्टर की बात करें तो इसमें रंग, वस्त्र फाइबर, मशीनरी और उत्पाद, कपड़ा और परिधान प्रक्रियाओं का डिजाइन और नियंत्रित करने की प्रक्रिया शामिल है। इसमें फैशनबल कपड़ों की मांग को ध्यान में रखते हुए बहुत ज्यादा रिसर्च, क्रिएटिविटी और इनोवेशन की जरूरत होती है। इसमें टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की यह शाखा उन सिद्धांतों का भी अध्ययन करती है जो कपड़ा फाइबर के

प्रकार के यार्न और टेक्सटाइल कपड़ों के निर्माण में किया जाता है। कपड़ा इंजीनियरिंग में, कपड़े को आकर्षक और फैशनबल बनाने पर जोर दिया जाता है। इसके लिए टेक्सटाइल इंजीनियर को काफी रिसर्च और एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। टेक्सटाइल इंजीनियर को नवाचार, अनुसंधान और रचनात्मकता जैसे कौशल की आवश्यकता होती है।

किस तरह का कोर्स करें

टेक्सटाइल इंडस्ट्री में करियर बनाने के लिए आपको 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायोलॉजी जैसे विषय में पढ़ाई करनी होगी। इसके बाद टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में बीई या बीटेक, टेक्सटाइल डिजाइनिंग में बीए, टेक्सटाइल डिजाइन में बीएससी, बैचलर ऑफ डिजाइन, डिप्लोमा इन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग या टेक्सटाइल केमिस्ट्री में बीटेक कर सकते हैं। वहीं आप इन कोर्सेज में एडवॉरंस डिप्लोमा, एमईए एमटेक और उसके बाद पीएचडी भी कर सकते हैं।

जॉब प्रोफाइल क्या है

इस इंडस्ट्री में आप मुख्य रूप से प्रोडक्शन कंट्रोल, प्रोडक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंजीनियरिंग प्रोसेस, सेल्स, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट, सुपरविजन आदि डिपार्टमेंट्स में काम कर सकते हैं। एक टेक्सटाइल इंजीनियर आम तौर पर इंजीनियरिंग प्रोसेस से जुड़ा होता है, जबकि अपैरल और गारमेंट्स की डिजाइनिंग और मेन्युफैक्चरिंग के लिए काम करने वाले प्रोफेशनल्स प्रोडक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं।

इन स्किल की जरूरत

अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपके अंदर कई स्किल का होना जरूरी है। जिसमें मुख्य रूप से कम्युनिकेशन रिकल्स, कम्यूटर स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी जरूरी हैं। इसके अलावा उनमें चीजों की बारीकियों पर ध्यान देने की क्षमता, लॉजिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी होनी भी जरूरी है।

करियर की संभावनाएं

कोर्स पूरा होने के बाद आप आप इस फील्ड में टेक्सटाइल मिल्स, एक्सपोर्ट हाउसेज, निटवेयर मेन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, टेक्सटाइल डाइंग एंड प्रिंटिंग यूनिट्स में काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप सरकार द्वारा प्रायोजित अथवा निजी सिल्व, हैंडलूम, जूट, खादी, क्राफ्ट डेवलपमेंट संस्थानों में काम कर सकते हैं। आप फैशन रीटेलर्स डिजाइन स्टूडियो और बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जैसे में भी काम कर सकते हैं।

सैलरी

टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा व डिग्री के बाद आप फ्रेशर के तौर पर अगर आप नौकरी करना चाहते हैं तो 30 से 45 हजार रुपये का शुरुआती वेतन आसानी से मिल जाता है। अनुभव के बाद, आप

आईआईटी से टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है, तो आपको शुरुआती वेतन काफी आकर्षक लग सकता है।



कटुआ जिला प्रशासन ने जनजातीय गौरव दिवस मनाया, भगवान बिरसा मुंडा को पुष्पांजलि अर्पित की



कटुआ, 15 नवंबर (हि.स.)। कटुआ जिला प्रशासन ने जनजातीय गौरव दिवस पर जनप्रतिनिधियों, जिला अधिकारियों, जनजातीय समुदाय के विशिष्ट व्यक्तियों और लाभार्थियों ने भगवान बिरसा मुंडा की विरासत का सम्मान किया और राष्ट्र निर्माण में जनजातीय समुदायों के योगदान को स्वीकार किया।

इस कार्यक्रम में कटुआ के विधायक डॉ. भारत भूषण, डीडीसी सदस्य नगरी संदीप मजोत्रा,

एडीडीसी कटुआ सुरिंदर मोहन शर्मा, डीपीओ आईसीडीएस कटुआ मोहम्मद सैयद खान, सीपीओ रंजीत ठाकुर, जिला अधिकारी, गणमान्य नागरिक और जनजातीय विशिष्ट व्यक्तियों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम की शुरुआत गणमान्य व्यक्तियों द्वारा भगवान बिरसा मुंडा को पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ हुई जिसमें उनके संघर्ष, बलिदान और जनजातीय आंदोलन में उनकी भूमिका के प्रति गहरा सम्मान व्यक्त

जम्मू नगर निगम ने जम्मू में पारंपरिक जल निकायों के जीर्णोद्धार हेतु पहल की शुरु

जम्मू, 15 नवंबर (हि.स.)। जम्मू नगर निगम ने अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी जल निकायों के जीर्णोद्धार और पुनरुद्धार हेतु एक व्यापक पहल शुरू की है। शहरीकरण और बढ़ती शुष्कता के कारण तालाबों, कुओं और पारंपरिक जल स्रोतों के तेजी से लुप्त होने के साथ, नगर निगम प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और उनके महत्व के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।

पारंपरिक जल तालाबों के संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए जम्मू नगर निगम अपने प्रयासों को और मजबूत कर रहा है। आज संग्रामपुर के दुर्गोचक क्षेत्र के वाई संख्या 75 में विधायक सुरेंद्र कुमार ने नगर आयुक्त डॉ. देवेश यादव के साथ एक ऐतिहासिक तालाब के संरक्षण और पूर्ण पुनर्निर्माण की आधारशिला रखी।

इस परियोजना के लिए कुल 23.36 लाख रुपये निर्धारित किए गए हैं। पुनरुद्धार योजना में तालाब की सफाई, रेलिंग लगाना, तालाब के चारों ओर पैदल मार्ग का निर्माण, सजावटी पौधे लगाना और उच्च गुणवत्ता वाले हरित तट विकसित करना शामिल है। इसका उद्देश्य गुलाशाय के पारिस्थितिक संतुलन को बहाल करना और इसे स्थानीय समुदाय के लिए एक स्वच्छ, हरित और आकर्षक मनोरंजन स्थल में बदलना है।

पुलिस ने कनाचक इलाके में हत्या का मामला सुलझाया, आरोपी को किया गिरफ्तार

जम्मू, 15 नवंबर (हि.स.)। जम्मू (ग्रामीण) पुलिस ने कनाचक इलाके में दर्ज एक हत्या के मामले को तेजी से सुलझाते हुए घटना के कुछ ही घंटों के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

गुरहा सिंधू, तहसील मढ़ में 14 नवंबर 2025 को एक हिंसक पारिवारिक जमीन विवाद ने दुखद रूप ले लिया जिसके परिणामस्वरूप एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया।

प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार विक्रम सिंह पुत्र झंडार सिंह अपनी पत्नी के साथ अपने खेत में काम कर रहे थे, तभी जमीन के मालिकाना हक को लेकर परिवार के सदस्यों के बीच बहस छिड़ गई। इस झड़प के दौरान आरोपी रणजीत सिंह कौशिक तीर पर एक ट्रैक्टर पर खेत में घुस गया और जानबूझकर विक्रम सिंह और उसकी पत्नी दोनों पर गोड़ी चढ़ा दी और फिर मौके से फरार हो गया।

दोनों पीड़ितों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। दुर्भाग्य से विक्रम सिंह की मौत हो गई जबकि उनकी पत्नी वेष्णो देवी का इलाज जारी है।

घटना के संबंध में कनाचक पुलिस स्टेशन में एफआईआर संख्या 165/2025 दर्ज की गई। जम्मू (ग्रामीण) पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कुछ ही घंटों में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और अपराध में शामिल ट्रैक्टर भी जब्त कर लिया। घटना के पूरे क्रम और उसके पीछे छिपे मकसद का पता लगाने के लिए आगे की जाँच जारी

राजेश गुप्ता ने नौगाम पुलिस स्टेशन विस्फोट की कड़ी निंदा की

श्रीनगर, 15 नवंबर (हि.स.)। राज्य अध्यक्ष, विश्व हिंदू परिषद (विहिप) जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख ने श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में 4 नवंबर 2025 की रात हुए भयावह विस्फोट की घोर निंदा की है। इसमें कई बहादुर पुलिसकर्मी शहीद हुए और कई घायल हुए जिसने पूरे समुदाय को स्तब्ध एवं शोकाकुल कर दिया है।

राजेश गुप्ता ने शहीदों के परिजनों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट की और घायल अधिकारियों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। उन्होंने नौगाम पुलिस स्टेशन की बहादुरी एवं समर्पण की भी प्रशंसा की जिसने हाल ही में कश्मीर के डॉक्टरों के नाम पर छुपे एक बड़े अंतरराज्यीय आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया था।

वेयर हाउस क्षेत्र में 50 लाख रुपये की लागत से बिजली की तारबंदी का काम किया शुरु



जम्मू, 15 नवंबर (हि.स.)। वरिष्ठ भाजपा नेता और जम्मू पूर्व विधानसभा क्षेत्र के विधायक युद्धवीर सेठी ने आज जम्मू के वेयर हाउस और आसपास के इलाकों में 50 लाख रुपये की लागत से बहुप्रतीक्षित बिजली की तारबंदी परियोजना का शुभारंभ किया।

इस अवसर पर बोलते हुए सेठी ने कहा कि बुनियादी ढाँचे का विकास सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस पहल का उद्देश्य उन निवासियों और व्यापारियों को लंबे समय से लंबित हार्दक प्रदान करना है जो वर्षों से सड़कों के उन्नयन की मांग

कर रहे हैं। युद्धवीर सेठी ने कहा कि जम्मू के सबसे व्यस्त व्यावसायिक क्षेत्रों में से एक में व्यापार को बढ़ावा देने और लोगों की आवाजही को सुगम बनाने के लिए सड़क संपर्क में सुधार आवश्यक है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह परियोजना क्षेत्र के समग्र बुनियादी ढाँचे को मजबूत करेगी और सुगम परिवहन सुविधाओं पर निर्भर व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देगी। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास पूर्ण पारदर्शिता के साथ गुणवत्तापूर्ण विकास सुनिश्चित

किया गया। सभा को संबोधित करते हुए विधायक डॉ. भारत भूषण ने आदिवासी अधिकारों और पहचान की रक्षा में बिरसा मुंडा के उल्लेखनीय योगदान पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि जनजातीय गौरव दिवस जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाने और उन्हें विकास में समान अवसर प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि करने का एक अवसर है। उन्होंने जनजातीय परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में जिला प्रशासन के प्रयासों की सराहना की। इसी बीच जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का सीधा प्रसारण भी किया गया जिसमें प्रधानमंत्री ने देश भर के जनजातीय समुदायों के उत्थान, शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका सहायता के लिए सरकार की पहलों के बारे में बताया।

उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने पुलिस स्टेशन के अंदर हुए विस्फोट पर व्यक्त किया गहरा दुःख

लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने शनिवार को श्रीनगर के एक पुलिस स्टेशन के अंदर हुए विस्फोट पर दुःख व्यक्त किया जिसमें 9 लोग मारे गए और 29 अन्य घायल हो गए।

उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने एक्स पर कहा कि श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए दुखद विस्फोट से गहरा दुःख हुआ है। अपनी जान गंवाने वालों के परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ।शुक्रवार देर रात श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में एक आकस्मिक विस्फोट हुआ जिसमें 9 लोग मारे गए और 29 अन्य घायल हो गए।

द्वद्द1यह विस्फोट उस समय हुआ जब अधिकारी सफेदपोश आतंकी मॉड्यूल मामले में जब्त किए गए विस्फोटकों के एक बड़े जखीरे से नमूने निकाल रहे थे।

बागवानी तकनीकों पर एक दिवसीय कौशल विकास कार्यशाला का आयोजन



कटुआ, 15 नवंबर (हि.स.)। संस्थागत नवाचार परिषद के तत्वावधान में राजकीय जीएलडीएम डिग्री कॉलेज हीरानगर में बागवानी तकनीकों पर एक दिवसीय कौशल विकास कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का आयोजन प्राचार्य डॉ. प्रज्ञा खन्ना के मार्गदर्शन और नेतृत्व के किया गया, जिसका उद्देश्य छात्रों में व्यावहारिक ज्ञान और रोजगारपरक कौशल को सुदृढ़ करना था।

प्रारंभ में प्राचार्य डॉ. प्रज्ञा खन्ना

गोवंश तस्करी प्रयास विफल, 18 गोवंशों को मुक्त करवाया



कटुआ, 15 नवंबर (हि.स.)। जिले में गोवंश तस्करोँ पर शिकंजा कसते हुए एसएसपी कटुआ मोहिता शर्मा की देखरेख में कटुआ पुलिस ने थाना राजबाग क्षेत्र से कुल 18 गोवंशों को बचाया। वहीं तस्करी में शामिल 02 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर 02 वाहनों को जब्त किया।

जानकारी के अनुसार एसएचओ थाना राजबाग अजय सिंह चिब के नेतृत्व में राजबाग की एक पुलिस टीम ने एनएचडब्ल्यू राजबाग क्षेत्र में नाका/जांच के दौरान दो संदिग्ध वाहनोँ जेके06सी-1973 और जेके02एबी-8677 को शक के

आधार पर जांच के लिए रोका जो कटुआ से जम्मू की ओर जा रहे थे। जांच के दौरान दोनों वाहनोँ में कुल 18 गोवंश बेरहमी से लदे पाए गए। जिसके बाद पुलिस ने ट्रकों से गोवंश को मुक्त करवाया और दोनों

वालकों को गिरफ्तार कर 02 ट्रकों को मौके पर ही जब्त कर लिया गया। वालकों की पहचान मोहम्मद यूनूस पुत्र बशीर अहमद निवासी मंजीन लोअर दवारा और तोफिम निसार पुत्र निसार हुसैन निवासी गांव सेमसमात राजौरी के रूप में हुई है। इस संबंध में थाना राजबाग में एफआईआर संख्या 222/2025 धारा 223 वीएनएस 11 पीसीए और एफआईआर 223/2025 धारा 223 वीएनएस 11 पीसीए अधिनियम के तहत दो तत्काल मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि इस मामले में आगे की जांच शुरू कर दी गई है।

लैंड बैंक विस्तार के लिए प्लग एंड प्ले मॉडल लागू करें, एमएसएमई इकाइयों के लिए होगा उपयोगी : मुख्यमंत्री

लखनऊ, 15 नवंबर।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए लैंड बैंक के विस्तार और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को त्वरित सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु प्लग एंड प्ले मॉडल को लागू करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। शनिवार को आयोजित एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिक परियोजनाओं के लिए प्लग्स और सतत उपलब्ध भूमि सुनिश्चित करने के लिए लीज रेंटल मॉडल को रेवेन्यू शेयरिंग के आधार पर आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि यह मॉडल उत्तर प्रदेश के लिए अत्यंत उपयोगी साबित हो सकता है और इसी आधार पर विस्तृत नीति तैयार की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि इस नीति का मुख्य फोकस एमएसएमई क्षेत्र पर हो, ताकि छोटे और मध्यम उद्योग बिना अतिरिक्त जटिलताओं के तुरंत उत्पादन शुरू कर सकें

बैठक में बताया गया कि प्रदेश



में औद्योगिक भूमि की दरें अपेक्षाकृत अधिक हैं और खासकर एनसीआर से जुड़े जिलों में यह दबाव अधिक महसूस होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भूमि की लागत उद्योगों के विस्तार, तकनीकी उन्नयन और नई इकाइयों की स्थापना के मार्ग में प्रमुख बाधा है। इसी कारण एमएसएमई के लिए किरायती आकार के भूखंडों और तैयार औद्योगिक शेड उपलब्ध कराना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि नए मॉडल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होगा है कि उद्योग भूमि खरीद और निर्माण संबंधी प्रक्रियाओं में समय और संसाधन खर्च करने के बजाय सीधे उत्पादन, मशीनरी स्थापना और रोजगार

केवीआईबी कटुआ द्वारा हीरानगर की बागोचक पंचायत में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

कटुआ, 15 नवंबर (हि.स.)। जम्मू-कश्मीर खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड ने हीरानगर की बागोचक पंचायत में एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया।

जिसका उद्देश्य क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को जम्मू-कश्मीर केवीआईबी द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं के बारे में जागरूक/संवेदनशील बनाना था।इस कार्यक्रम में विभिन्न विभागों/बैंकों के प्रतिनिधियों जैसे कि एसबीआई के अग्रणी जिला प्रबंधक, स्वरोजगार के लिए एफपीओ प्रतिनिधि, हस्त कला केंद्र हीरानगर के प्रभारी, क्षेत्र के पूर्व सरपंच/पंचों और बड़ी संख्या में बेरोजगार युवाओं ने भाग लिया।

सभी विभागों ने युवाओं और प्रतिभागियों को अपनी योजनाओं



के बारे में जागरूक किया और स्वरोजगार उद्यम स्थापित करके सरकारी योजनाओं द्वारा प्रदान किए जा रहे अवसरों का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। जेके केवीआईबी कटुआ के जिला अधिकारी सुरिंदर पॉल शर्मा ने सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया और केवीआईबी की योजनाओं के बारे में विस्तार से

बताया। उन्होंने नवोदित उद्यमियों को पीएमईजीपी और जेकेआरईजीपी के तहत वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने और इस प्रक्रिया में आवश्यक अन्य प्रक्रियाओं की जानकारी दी। जिन नए उद्यमियों को बैंकों द्वारा वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है, उन्हें स्वीकृति पत्र भी वितरित किए गए।

कश्मीर संभागीय आयुक्त, श्रीनगर उपायुक्त ने एसएमएचएस और उजाला अस्पतालों का दौरा किया



श्रीनगर, 15 नवंबर। संभागीय आयुक्त कश्मीर अंशुल गर्ग ने श्रीनगर के उपायुक्त अक्षय लाभरू के साथ आज एसएमएचएस अस्पताल और उजाला अस्पताल का दौरा किया और नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए आकस्मिक विस्फोट में घायल हुए लोगों का हालचाल जाना।

इस दौरान, संभागीय आयुक्त को घायलों की स्थिति, उन्हें दिए जा रहे उपचार और उनके स्वास्थ्य लाभ की प्रगति के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने संबंधित चिकित्सा अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सभी

घायलों को गुणवत्तापूर्ण उपचार, समय पर दवा और सर्वोत्तम संभव चिकित्सा सुविधाएँ मिलें। संभागीय आयुक्त ने घायलों से बातचीत की, उनका हालचाल पूछा और आश्वासन दिया कि प्रशासन उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करेगा। अधिकारियों ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की।

नगरोटा पुलिस स्टेशन ने बहु-राज्यीय साइबर धोखाधड़ी का भंडाफोड़ किया, 2.27 करोड़ बरामद

जम्मू, 15 नवंबर (हि.स.)। जम्मू (ग्रामीण) पुलिस ने ऑनलाइन धोखेबाजों द्वारा धोखाधड़ी से निकाले गए 2,27,45,264/- बरामद करके एक बड़ी सफलता हासिल की है। यह मामला 10.04.2025 को शुरू हुआ जब खालिद हसन पुत्र गुलाम हसन निवासी दलपतियाँ मोहल्ला जम्मू द्वारा पुलिस स्टेशन नगरोटा में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी। उन्होंने बताया कि 08.04.2025 को जब वे सिधरा में थे तो उन्हें उनके भाई साजिद हसन का फोन आया जिसमें उन्होंने 54,00,000/- की तत्काल राशि मांगी थी।

अनुरोध पर कार्रवाई करते हुए शिकायतकर्ता ने अपने भाई के पक्ष में जम्मू-कश्मीर बैंक से 54 लाख का ऋण प्राप्त किया। हालाँकि 10.04.2025 को उसके भाई ने उसे सूचित किया कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज एप्लिकेशन के माध्यम से निवेश

की गई उक्त ऋण राशि सहित 2 करोड़ से अधिक की राशि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा धोखाधड़ी से निकाल ली गई है।

शिकायत के बाद पीड़ित को राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 के माध्यम से ऑनलाइन धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराने की सलाह दी गई। एनसीसीआरपी पोर्टल के माध्यम से पावती संख्या 31404250002762 के तहत दर्ज की गई शिकायत में आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज प्लेटफॉर्म पर धोखाधड़ीपूर्ण व्यापारिक गतिविधियों के माध्यम से 2,27,45,264/- की साइबर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था।

जांच के दौरान पीड़ित और संदिग्ध धोखेबाजों के बैंक स्टेटमेंट प्राप्त किए गए और उनका विश्लेषण किया गया। यह पाया गया कि गबन की गई राशि संदिग्धों द्वारा संचालित काले खातों में स्थानांतरित कर दी गई थी।

भाजपा ने डोडा और कटुआ में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया

जम्मू, 15 नवंबर (हि.स.)। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम में भाजपा जिला डोडा ने पुराने बस स्टैंड पर एक भव्य समारोह का आयोजन किया। यह कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम का हिस्सा था और इसमें डोडा भर के नागरिकों की भारी भागीदारी देखी गई।

भाजपा जम्मू-कश्मीर के राज्य सचिव पवन शर्मा ने डोडा जिले की एक संघर्षग्रस्त क्षेत्र से शांति और एकता के प्रतीक के रूप में परिवर्तन के लिए प्रशंसा की।

उन्होंने वंदे मातरम के देशभक्तिपूर्ण उत्साह को प्रतिबिम्बित करने में डोडा की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन और भारतीय स्वतंत्रता



संग्राम के दौरान इस गीत के गहरे ऐतिहासिक महत्व को रेखांकित किया और बताया कि कैसे इसने स्वतंत्रता संग्राम में राष्ट्र को एकजुट किया।

शर्मा ने राष्ट्रीय प्रतीकों और एकता को कमजोर करने के लिए नेशनल कॉन्फेंस, पीडीपी और कांग्रेस नेतृत्व की भी आलोचना की। उन्होंने जोर देकर कहा कि जम्मू-कश्मीर के लोग अब पहले से कहीं ज्यादा समझदार हो गए हैं और ऐसी

टिप्पणियों के पीछे के असली मकसद को पूरी तरह समझते हैं।

भाजपा जिला अध्यक्ष बाबू राम शर्मा ने इस बात पर जोर दिया कि यह आयोजन भारत की राष्ट्रीय पहचान और उसकी अटूट देशभक्ति की भावना के प्रति डोडा की अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि डोडा के लोग भारत की समृद्ध विरासत के गौरवशाली संरक्षक हैं और हमेशा एकता और राष्ट्रीय गौरव के स्तंभ रहे हैं।

संपादकीय

माँग जायज

उधमपुर में दूषित कफ सिरप पीने से विकलांग हुए बच्चों के अभिभावकों द्वारा उठाई गई मुआवजे की माँग पूरी तरह जायज है क्योंकि प्रभावित लोगों की इस तकलीफ़ के लिए कहीं न कहीं सरकार ज़िम्मेदार है क्योंकि बाज़ार में दवाओं की सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी केंद्र शासित प्रदेश सरकार के कंधों पर है। गौरतलब है कि 2०19 के अंत और 2020 की शुरुआत के बीच, उधमपुर के रामनगर इलाके में कम से कम 12 बच्चों की कथित तौर पर सिरप पीने से मौत हो गई, जबकि कई अन्य स्थायी रूप से विकलांग हो गए। सामने आ रही रिपोर्टों से आश्चर्यजनक रूप से पता चला है कि ऐसे दो स्थायी रूप से विकलांग बच्चों के अभिभावकों को अभी तक सरकार से कोई मुआवज़ा नहीं मिला है। यह चौंकाने वाला है क्योंकि एक कल्याणकारी राज्य होने के नाते सरकार को कम से कम प्रभावित परिवारों को पर्याप्त मुआवज़ा देकर न्याय सुनिश्चित करना चाहिए था क्योंकि वे जिस पीड़ा से गुज़र रहे हैं, वह केवल संबंधित सरकारी एजेंसियों के उदासीन रवैये के कारण है, जो यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं कि कोई भी नकली दवा उपभोक्ताओं तक न पहुँचे। दुर्भाग्य से, प्रभावित माता–पिता ने कथित तौर पर कहा है कि उनके बच्चे देखने, सुनने और बोलने की क्षमता खो चुके हैं, लेकिन सरकार उनके दर्द को भूल गई है क्योंकि कोई मुआवज़ा नहीं दिया गया है, जो सत्ता में बैठे लोगों की उदासीनता की पराकाष्ठा को दर्शाता है। हितधारकों ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से इस मामले में हस्तक्षेप करने और उचित न्याय सुनिश्चित करने का आग्रह किया है, इसलिए यह ज़रूरी हो जाता है कि इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाए क्योंकि माता–पिता का दुख असहनीय है। इसलिए यह ज़रूरी है कि सरकार विकलांग बच्चों के परिवारों को उचित मुआवज़ा प्रदान करे क्योंकि मृतक बच्चों के परिवारों को मुआवज़ा पहले ही मिल चुका है। यह बताना ज़रूरी है कि कथित तौर पर विकलांग हुए छह बच्चों में से चार को विकलांगता प्रमाण पत्र मिल गए हैं, जबकि दो परिवारों ने आवेदन ही नहीं किया था। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि इस तरह के जहरीले उत्पाद को बाज़ार में आने देना आपराधिक लापरवाही है और इसलिए संबंधित सरकारी एजेंसी की इस चूक को देखते हुए, प्रभावित बच्चों के गरीब माता–पिता को न्याय दिलाना और उनकी जायज़ माँग पूरी करना और बिना किसी देरी के पर्याप्त मुआवज़ा प्रदान करना, यह जिम्मेदारी सत्ता में बैठे लोगों की है।

बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत और लालूराज का स्याह अतीत

विक्रम उपाध्याय

साल 1990 में भारतीय राजनीति में दो बड़ी घटनाएं हुईं। विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने उस साल सत्ताईस प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान के साथ मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की और उसी साल तमाम तिकड़मों के साथ लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। यूं तो मंडल आयोग को लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुए लेकिन बिहार में इसके कारण वर्ग संघर्ष शुरू हुआ। अगड़े–पिछड़े के बीच कभी न खत्म होने वाली नफरत की खाई खोद दी गई। मुख्यमंत्री के नाते लालू प्रसाद यादव ने इसे खत्म करने के बजाय इसको हवा दी और पूरे दस साल जातीय नरसंहार का सिलसिला चलने दिया। उस दौरान राह चलते लोगों की जातियां पूछकर टुकाई की जाती रही और सत्ता में बैठे लालू इस संघर्ष का राजनीतिक लाभ लेते रहे। चारा घोटाले में नाम आने के बाद लालू प्रसाद यादव को कुर्सी छोड़नी पड़ी और साल 2005 आते–आते बिहार ने लालू परिवार के शासन से जो एक बार तौबा की तो फिर उस तरफ नहीं देखा। साल 2025 के ताजा चुनाव परिणाम में राजद के सफ़ाए के पीछे प्रारंभिक कारण सिर्फ़ और सिर्फ़ लालू राज के अत्याचार से बचे रहने का फैसला ही है।

राजनीतिक विश्लेषक भले ही जीत–हार के अलग–अलग कारण गिना रहे हों लेकिन नीतीश कुमार के प्रति विश्वास से कोई बड़ा कारण नहीं हो सकता है। उस पर से भाजपा का केंद्र की सत्ता में रहना, सोने पर सुहगे की तरह काम कर रहा है। मोदी और नीतीश ने मिलकर बिहार का ऐसा एकजुट समाज बनाया है, जिसमें सभी वर्ग के लोग सुरक्षित महसूस करते हैं, यहां तक कि मुस्लिम आबादी भी। भले आर्थिक आंकड़ों में यह बिहार किसी शीर्ष राज्य की श्रेणी में नहीं आता है लेकिन चैन से सोने और मनमाफ़िक काम करने की आजादी की कोई गणना हो तो बिहार पहले पांच राज्यों में जरूर आ सकता है।

नीतीश कुमार ने बीस वर्षों के अपने कार्यकाल में जो सबसे बड़ी मिसाल

नए भारत के विराट नेतृत्व के पक्ष में बिहार का जनादेश

–आचार्य संजय तिवार

बिहार के चुनाव परिणाम आ चुके। जनादेश की आधी में भारत विरोधी जुमलों का नामोनिशान मिट गया। बिहार की जनता ने साफ संदेश दे दिया कि ज्ञान और संस्कृति की धरती पर अपशब्दों, गलियों, संस्कृति पर आघात और सनातन विरोधी साजिशकर्ताओं के लिए अब कोई जगह नहीं है। बिहार ने नए भारत के विराट नेतृत्व में गजब की आस्था व्यक्त किया है। नरेन्द्र मोदी पर भरोसा, अमित शाह की रणनीति और एनडीए के सभी दलों में अद्भुत सामंजस्य ने भारत की राष्ट्रीय राजनीति को भी स्थायित्व प्रदान किया है। पूरे चुनाव प्रबंधन की रणनीति के शिखी अमित शाह की दूरगामी दृष्टि है जिसने इस एक चुनाव के माध्यम से ही केंद्र की सरकार की भी बहुत सलीके से और मजबूत बना दिया है। गाहे–बगाहे केंद्र सरकार की अस्थिरता के सपने देखने वालों की अब नींद जरूर टूट जाएगी। चुनाव आयोग



कायम की है, वह है, तटस्थता के साथ सरकार का संचालन और बिना राग–द्वेष का राजनीतिक व्यवहार। दूसरी तरफ लालू परिवार ने अपने पंद्रह साल के शासन में राज्य को न सिर्फ अशांत क्षेत्र में बदल दिया बल्कि खुद के लिए भ्रष्टाचार का स्वर्ग स्थापित कर लिया। ना तो उन्होंने सामाजिक मर्यादा का ख्याल रखा और ना किसी कानून की परवाह की। सत्ता के अपने सहयोगियों से भी वसूली करने में नहीं हिचके। कांति सिंह और रघुनाथ झा जैसे वरिष्ठ सहयोगियों से भी सांसद, मंत्री बनाने के एवज में जमीन लिखवा ली। कहा तो यह भी गया कि लालू प्रसाद यादव ने बिहार के समर्थ लोगों के खिलाफ अपहरण और फिरोती के कारोबार को अपनी देखरेख में चलवाया।

हालात तो यहां तक पहुंच गई थी कि अपराधियों ने लोगों की अवकाश निधि और पेंशन को हड़पने के लिए भी अपहरण का रास्ता अपनाया। क्या उस बिहार की कोई दोबारा कल्पना करना चाहेगा? कभी नहीं। बिहार के लोगों के मन में हमेशा के लिए यह भाव घर कर गया है कि राजद को सत्ता में लाने के लिए वोट करने का मतलब फिर से साल 1990 के बाद के काल खंड में बिहार को पहुंचाना है।

ऐसा नहीं है कि बिहार, नीतीश के

समेत देश की लगभग सभी संवैधानिक संस्थाओं को बार बार कटघरे में खड़ा कर लोगों को भटकाने की राहुल गांधी की योजना को भी इस परिणाम ने ध्वस्त कर दिया है। इस चुनाव में मोदी और नीतीश को लेकर महिलाओं ने जो उत्साह दिखाया वह अभूतपूर्व कहा जाएगा।

वास्तव में बिहार चुनाव की अवधि और इसके परिणाम की गहराई को देखने से कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ रहे हैं। यह चुनाव वास्तव में एक लिटमस परीक्षण ही था जिसकी वास्तविकताओं को भी सामने लाने में डर लग रहा था। विपक्षी इंडी गटबंधन की धमकी और भाषा ने अनेक सर्वे एजेंसियों को वास्तविकता परोसने नहीं दिया। सब डरे हुए थे। जब बिहार में चुनाव प्रचार शुरू हुआ था तब वोट चोरी के आरोपों के साथ अत्यंत उपद्रवी अंदाज में कांग्रेस और राजद ने अभियान चलाया। राहुल गांधी की आक्रामकता से अब सभी परिचित हैं। उन लोगों को यह लग रहा था कि बिहार

के नौजवान उनकी आक्रामकता और शैली के प्रभाव में जरूर आएंगे और नेपाल की जेन जेड क्रांति जैसा कुछ हो जाएगा। बिहार में दक्षिण के उन नेताओं के साथ मंच सजाए गए जो बाकायदा अपने राज्य में हिंदुत्व उन्मूलन अभियान चला रहे हैं।

यहां एक और महत्वपूर्ण घटना हुई। बिहार का बेटा बनकर प्रशांत किशोर का चुनावी शंखनाद और जन जागरण। उनकी घोषणा थी कि इस बार नीतीश कुमार की पार्टी जदयू 25 से भी कम सीटों में सिमट जाएगी। यदि 25 से ज्यादा सीटें जद यू को मिलीं तो वे राजनीति छोड़ देंगे। बिहार चुनाव से पहले तक तक अलग –अलग राजनीतिक दलों के लिए चुनावी रणनीति की दुकान चलाने वाले प्रशांत किशोर को लगा था कि बिहार के वास्तविक मुद्दों को उभार कर, जंगलराज को दोहराने का डर दिखा कर जनता को वह अपने पक्ष में कर लेगे। इसी सपने के साथ उन्होंने सभी 243

राजनीतिक विश्लेषक भले ही जीत–हार के अलग–अलग कारण गिना रहे हों लेकिन नीतीश कुमार के प्रति विश्वास से कोई बड़ा कारण नहीं हो सकता है। उस पर से भाजपा का केंद्र की सत्ता में रहना, सोने पर सुहागे की तरह काम कर रहा है। मोदी और नीतीश ने मिलकर बिहार का ऐसा एकजुट समाज बनाया है, जिसमें सभी वर्ग के लोग सुरक्षित महसूस करते हैं, यहां तक कि मुस्लिम आबादी भी। भले आर्थिक आंकड़ों में यह बिहार किसी शीर्ष राज्य की श्रेणी में नहीं आता है लेकिन चैन से सोने और मनमाफ़िक काम करने की आजादी की कोई गणना हो तो बिहार पहले पांच राज्यों में जरूर आ सकता है।

नहीं होगा, जहां मॉल न खुल गया हो। जहां तनिष्क, टाटा और रिलायंस के शोरूम न हों। किसी भी हाईवे से निकल कर देखिए, नए और बड़े निर्माण होते दिखाई पड़ जाएंगे। किसी चौराहे पर खड़े हो जाइए, महिला पुलिस बहुतायत में दिखाई पड़ जाएंगी। अधिकतर थानेदार, आपको उस जाति वर्ग के मिलेंगे, जिनको राजद अपनी बपौती बताती रहती थी। यह विकास के साथ सामाजिक विश्वास का आगाज है।

नीतीश कुमार और भाजपा के बीच के प्रगाढ़ संबंध की उम्र अब तीस साल से अधिक हो गई है। बीच के दो छोटे–छोटे समयवाधि को निकाल दे तो यह संबंध लगातार मजबूती की ओर ही बढ़ता गया है। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने जो नीतीश कुमार के साथ सद्भाव और विश्वास का संबंध स्थापित किया था, उसे लगातार प्रधानमंत्री मोदी आगे बढ़ा रहे हैं। सामाजिक न्याय के सभी प्रयोगों से लेकर बिहार के आर्थिक विकास के लिए पीएम मोदी ने नीतीश कुमार और बिहार के लिए संसाधनों की कमी नहीं होने दी है। आवास, इलाज और भूख की कमी से निबटने के उपायों में स्वयं प्रधानमंत्री मोदी अपनी ओर से पहल करते रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बिहार जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, उसे देखकर कोई भी

सीटों पर जनसुराज के प्रत्याशी खड़े कर दिए। प्रशांत किशोर की बातों और उनके मुद्दों से जनता आकर्षित तो हुई लेकिन जनता को इसके लिए प्रशांत किशोर की पार्टी पर भरोसा नहीं हुआ। उभरे हुए ये मुद्दे लहलहाती फसल बन गए एनडीए की खलिहान की फसल बन गए। 20 वर्ष पुराने जंगलराज की कहानियों ने बिहार के युवाओं और महिलाओं को विकल्प तलाशने पर विवश कर दिया। परिणाम यह हुआ कि जनता के सामने सबसे विश्वसनीय चेहरे के रूप में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ही नजर आए। रणनीति के साथ मगध की धरती पर गृहमंत्री अमित शाह ने मैदान में अपनी संतुलित और सुदृढ़ सेना उतार दी। भाजपा, जदयू के अलावा चिराग पासवान, जीतनराम मांझी और भूपेंद्र कुशवाहा जैसे बिहारी नेतृत्व को साझा सेना देकर सामने रखा। प्रबंधन में सीआर पाटिल के साथ केशव मोर्य की टीम लगा दी।

प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने बिहार को सांस्कृतिक धरातल पर मथा। लोक पर्व छठ को वैश्विक सम्मान देते और दिलाते

अंदाज लगा सकता है कि अगले दस साल में कनेक्टिविटी के मामले में बिहार किसी भी राज्य को मात दे सकता है। बिहार के लगभग सभी बड़े शहर हवाई मार्ग से जुड़ने जा रहे हैं। एक साथ दस नए एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है। बिहार को गरीब राज्य कह कर चिढ़ाने वाले लोग एक बार यह जानकारी जरूर कर लें कि बिहार में कितनी ऐसी कंपनियां काम कर रही है, जिनका प्रबंधन किसी और राज्य से होता है।

एनडीए को 200 सीटें यदि बिहार की जनता ने दी है, तो उसके पीछे सिर्फ महिलाओं को दी गई दस हजार की आर्थिक मदद नहीं है। राजद ने तो अपने घोषणा पत्र में तीन गुना राशि 14 जनवरी को देने का ऐलान कर दिया था। हर परिवार को एक नौकरी देने का प्रस्ताव रख दिया था। बिहार की जनता पैसे पर बिक कर वोट करने नहीं गई थी। इतना भारी जनमत वह मोदी और नीतीश में विश्वास जताने के लिए देने गई थी। बिहार के इस चुनाव परिणाम का विश्लेषण इस डायलॉग के साथ पूरा होना चाहिए कि यह लालू परिवार के डर के आगे एनडीए पर विश्वास की जीत है।

(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

हुए बिहार में विकास के नए आयाम दिखाए। महिलाओं के लिए अलग से भी नई योजनाएं लाई गईं। नीतीश कुमार के नेतृत्व पर भरोसा जताया। बिहार के परिणाम ने नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को बहुत मजबूत कर दिया है। भाजपा के बिहार प्रभारी और केंद्रीय शिक्षांत्री धर्मेन्द्र प्रधान कहते हैं कि जनता ने पिछले 20 साल के काम, पिछले साढ़े 11 साल की प्रधानमंत्री की नीतियों और जंगलराज तथा कुशासन के इतिहास को परखा और तुलना करने के बाद हम पर फिर से भरोसा जताया है।यहां यह लिखना बहुत समीचीन लगता है कि बिहार के विकास मॉडल के ब्रांड एंबेसडर स्वयं तेजस्वी यादव उसी रात बन गए थे जिस रात पटना में लोकनायक ब्रिज या कहें कि मरीन ड्राइव पर डांस करते नजर आए। दरअसल, तेजस्वी यह समझ ही नहीं सके कि उनके पिता के कार्यकाल वाले दौर से निकल चुके बिहार के 20 वर्षों के विकास का ही परिणाम है कि वे आधी रात को बिल्कुल निडर होकर यह डांस कर रहे हैं।

समाज को राह दिखाता है मीडिया

राष्ट्रीय प्रेस दिवस (16 नवम्बर) पर विशेषरमेश सराफ धमोरा

देश को आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली पत्रकारिता आजादी के बाद भी अलग–अलग परिदृश्यों में अपनी सार्थक जिम्मेदारियों को निभा रही है लेकिन मौजूदा दौर में पत्रकारिता दिनों–दिन मुश्किल बनती जा रही है। जैसे–जैसे समाज में अत्याचार, भ्रष्टाचार, दुराचार और अपराध बढ़ रहा है। पत्रकारों पर हमले की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। मीडिया और पत्रकारों पर हमला वही करते या करवाते हैं जो इन बुराइयों में डूबे हुए हैं। ऐसे लोग दोहरा चरित्र जीते हैं। मीडिया जब इनके काले कारनामों की पोल खोलने लगता है तो ये बीखला जाते हैं और उन पर हमले करवाते हैं। पुलिस और शासन तंत्र भी इन्हीं का साथ देते हैं। दिखावे के तौर पर मामला दर्ज कर लिया जाता है लेकिन होता कुछ नहीं। ये हालात चिन्तान्जनक है।

भारत में हर वर्ष 16 नवम्बर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। यह दिन भारत में एक स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस की मौजूदगी का प्रतीक है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस, प्रेस की

स्वतंत्रता एवं जिम्मेदारियों की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करता है। प्रथम प्रेस आयोग ने भारत में प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा एवं पत्रकारिता में उच्च आदर्श कायम करने के उद्देश्य से एक प्रेस परिषद की कल्पना की थी। परिणाम स्वरूप 4 जुलाई 1966 को भारत में प्रेस परिषद की स्थापना की गई जिसने 16 नवम्बर 1966 से अपना विधिवत कार्य शुरू किया। तब से लेकर आज तक प्रतिवर्ष 16 नवम्बर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस पत्रकारों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से स्वयं को फिर से समर्पित करने का अवसर प्रदान करता है।

मीडिया को समाज का दर्पण एवं दीपक दोनों माना जाता है। चाहे वे समाचार पत्र हों या समाचार चैनल, उन्हें मूलतः समाज का दर्पण माना जाता है। दर्पण का काम है वह समाज की हू–ब–हू तस्वीर समाज के सामने पेश कर सके।

परन्तु कभी–कभी निहित स्वार्थों के कारण ये समाचार मीडिया समतल दर्पण की जगह उतल या अवतल दर्पण की तरह काम करने लग जाते हैं। इससे समाज की उल्टी, अवास्तविक,

काल्पनिक एवं विकृत तस्वीर भी सामने आ जाती है। तात्पर्य यह है कि खोजी पत्रकारिता के नाम पर आज पीली व नीली पत्रकारिता हमारे कुछ पत्रकारों के गुलाबी जीवन का अभिन्न अंग बनती जा रही है। भारतीय प्रेस परिषद ने अपनी रिपोर्ट में कहा भी है कि भारत में प्रेस ने ज्यादा गलतियां की है एवं अधिकारियों की तुलना में प्रेस के खिलाफ अधिक शिकायतें दर्ज हैं।

वर्तमान समय में पत्रकारिता का क्षेत्र व्यापक हो गया है। पत्रकारिता जन–जन तक सूचनात्मक, शिक्षाप्रद एवं मनोरंजनात्मक संदेश पहुंचाने की कला एवं विधा है। समाचार पत्र एक ऐसी उत्तर पुस्तिका के समान है जिसके लाखों परीक्षक एवं अनगिनत समीक्षक होते हैं। अन्य माध्यमों के भी परीक्षक एवं समीक्षक उनके लक्षित जनसमूह ही होते हैं। तथ्यपरकता, यथार्थवादिता, संतुलन एवं वस्तुनिष्ठता इसके आधारभूत तत्व हैं। परन्तु इनकी कमियां आज पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत बड़ी त्रासदी साबित होने लगी हैं।

पत्रकार चाहे प्रशिक्षित हो या गैर प्रशिक्षित, यह सबको पता है कि पत्रकारिता में तथ्यपरकता होनी चाहिए। परन्तु तथ्यों को तोड़–मरोड़ कर, बढ़ा–चढ़ा कर या घटाकर सनसनी बनाने की प्रवृति आज पत्रकारिता में बढ़ने लगी है। रिपोर्टर्स विदआउट बॉर्डर्स (आरएसएफ) के 2025 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 180 देशों में से 151वें स्थान पर है। यह साल 2024 में 159वें और 2023 में 161वें स्थान से थोड़ा बेहतर है। लेकिन भारत अभी भी बहुत गंभीर प्रेस स्वतंत्रता श्रेणी में है। भारत नेपाल (90वां), मालदीव (104वां), श्रीलंका (139वां) और बांग्लादेश (149वां) जैसे पड़ोसी देशों से नीचे है। नॉर्वे, एस्टोनिया और नीदरलैंड प्रेस स्वतंत्रता में वैश्विक स्तर पर शीर्ष तीन प्रदर्शनकारी हैं। पहली बार, वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता को आर्थिक दबावों के बढ़ने के कारण कठिन स्थिति में देखा जा रहा है।

भारत जैसे विकासशील देशों में मीडिया पर जातिवाद और सम्प्रदायवाद करने और गरीबी तथा अन्य सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ाई में लोगों की सहायता करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि लोगों का एक बहुत बड़ा वर्ग पिछड़ा और अनभिज्ञ है। इसलिये यह

आज की जरूरी है कि आधुनिक विचार कर, बढ़ा–चढ़ा कर या घटाकर सनसनी बनाने की प्रवृति आज पत्रकारिता में बढ़ने लगी है। रिपोर्टर्स विदआउट बॉर्डर्स (आरएसएफ) के 2025 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 180 देशों में से 151वें स्थान पर है। यह साल 2024 में 159वें और 2023 में 161वें स्थान से थोड़ा बेहतर है। लेकिन भारत अभी भी बहुत गंभीर प्रेस स्वतंत्रता श्रेणी में है। भारत नेपाल (90वां), मालदीव (104वां), श्रीलंका (139वां) और बांग्लादेश (149वां) जैसे पड़ोसी देशों से नीचे है। नॉर्वे, एस्टोनिया और नीदरलैंड प्रेस स्वतंत्रता में वैश्विक स्तर पर शीर्ष तीन प्रदर्शनकारी हैं। पहली बार, वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता को आर्थिक दबावों के बढ़ने के कारण कठिन स्थिति में देखा जा रहा है।

भारत जैसे विकासशील देशों में मीडिया पर जातिवाद और सम्प्रदायवाद करने और गरीबी तथा अन्य सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ाई में लोगों की सहायता करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि लोगों का एक बहुत बड़ा वर्ग पिछड़ा और अनभिज्ञ है। इसलिये यह आज की जरूरी है कि आधुनिक विचार

उन तक पहुंचाए जाएं और उनका पिछड़ापन दूर किया जाए ताकि वे सजग भावत का हिस्सा बन सकें। इस दृष्टि से मीडिया की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है।

आजादी से पहले पत्रकारिता एक मिशन थी। आजादी के बाद यह एक व्यवसाय बन गई। आपातकाल के दौरान जब प्रेस पर सेंसर लगा था, तब पत्रकारिता एक बार फिर थोड़े समय के लिए भ्रष्टाचार मिटाओं अभियान को लेकर मिशन बन गई थी। धीरे–धीरे पत्रकारिता प्रोडक्शन से सेन्सेशन एवं सेन्सेशन से कमीशन बन गई है। परन्तु इन तमाम सामाजिक बुराइयों के लिए सिर्फ़ मीडिया को दोषी ठहराना उचित नहीं है। समाज में हमेशा बदलाव आता रहता है। विकल्प उत्पन्न होते रहते हैं। ऐसी अवस्था में समाज असमंजस की स्थिति में आ जाता है। इस स्थिति में मीडिया समाज को नई दिशा देता है। मीडिया समाज को प्रभावित करता है, लेकिन कभी–कभी येन–कैन प्रकारेण मीडिया समाज से प्रभावित होने लगता है।

हालांकि प्रेस जहां एक तरफ जनता का आईना होता है। वहीं दूसरी ओर प्रेस जनता को गुमराह करने में भी

सक्षम होता है। इसीलिए प्रेस पर नियन्त्रण रखने के लिए हर देश में अपने कुछ नियम और सगटन होते हैं। जो प्रेस को एक दायरे में रहकर काम करते रहने की याद दिलाते हैं। प्रेस की आजादी को छीनना भी देश की आजादी को छीनने की तरह ही होता है। चीन, जापान, जर्मनी, पाकिस्तान जैसे देशों में प्रेस को पूर्णतः आजादी नहीं दी गई है। यहां की प्रेस पर सरकार का सीधा नियंत्रण है। इस लिहाज से हमारा देश भारत उनसे बहुत अधिक ठीक है। आज मीडिया के किसी भी अंग की बात कर लीजिये हर जगह दाव–पेंच का असर है। खबर से ज्यादा आज खबर देने वाले का महत्व हो चला है। पक्षपात होना मीडिया में भी कोई बड़ी बात नहीं है। जो लोग मीडिया से जुड़ते हैं, अधिकांश का उद्देश्य जन जागरूकता फैलाना न होकर अपनी धाक जमाना ही अधिक होता है।

कुछ लोग खुद को स्थापित करने लिए भी मीडिया का रास्ता चुनते हैं। कुछ लोग चंद पत्र–पत्रिकाओं में लिखकर अपने समाज के प्रति अपने दायित्व की इतिश्री कर लेते हैं। छद्म नाम से भी मीडिया में लोगों के आने का प्रचलन बढ़ा है। सत्य को स्वीकारना इतना आसान नहीं होता है और इसीलिए कुछ लोग सत्य उद्धाटित करने वाले से बैर रखते हैं। लेकिन फिर कुछ लोग मीडिया में अपना सबकुछ दांव पर लगाकर भी इस रास्ते को ही चुनते हैं और अफसोस की फिर भी उनकी वह

पूछ नहीं होती जिसके की वे हकदार होते हैं।

दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों में कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के साथ प्रेस को वैथा खभा माना जाता है। प्रेस इनको जोड़ने का काम करती है। प्रेस की स्वतंत्रता के कारण ही कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका को मजबूती के साथ आम आवाम की भावना को अभिव्यक्त करने का अवसर हासिल हुआ है। कभी कभी प्रेस पर तिल को ताड़ बनाने का आरोप लगाया जाता है हालाँकि यह पूरी तरह सच नहीं है। आजादी के बाद प्रेस पर बहुत जिम्मेदारी आ गई।

खबरों में पक्षधरता एवं असंतुलन भी प्रायः देखने को मिलता है। इस प्रकार खबरों में निहित स्वार्थ साफ झलकने लग जाता है। आज समाचारों में विचार को मिश्रित किया जा रहा है। समाचारों का सम्पादकीयकरण होने लगा है। विचारों पर आधारित समाचारों की संख्या बढ़ने लगी है। इससे पत्रकारिता में एक अस्वास्थ्यकर प्रवृत्ति विकसित होने लगी है। समाचार विचारों की जननी होती है। इसलिए समाचारों पर आधारित विचार तो स्वागत योग्य हो सकते हैं, परन्तु विचारों पर आधारित समाचार अभिशाप की तरह होते हैं।

(लेखक, हिन्दुस्थान समाचार से संबद्ध हैं।)

किसानों के लिए बायर ने लॉन्च किया मौसम जोखिम से बचाव का नया कवच ‘अलिवियो’

एजेंसी नई दिल्ली। बायर ने अपना डिजिटल समाधान ‘अलिवियो’ लॉन्च किया है। यह स्पेनिश शब्द है, जिसका अर्थ है ‘राहत’। कंपनी ने इसमें नुकसान को कम करने की प्रक्रिया को नए सिरे से डिजाइन किया है। किसानों को ‘अलिवियो’ मोबाइल ऐप के जरिए इंटीग्रेटेड, वैल्यू-एडिड सेवा के रूप में ऐसी जानकारीा प्रदान की जाएगी, जिनके आधार पर वे तत्काल कदम उठा सकते हैं। कंपनी ने जारी एक बयान में कहा कि किसानों को केंद्र में रखकर तैयार हो रहा है, जो डिजिटल युग का सशक्त कृषि मॉडल है। बायर ने पारंपरिक बीमा उत्पादों से अलग इश्योरेंस इकोसिस्टम एवं सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी युनाइटेड इंडिया इश्योरेंस के साथ मिलकर लॉन्च किए गए ‘अलिवियो’ में हाई-रेजॉल्यूशन सेटेलाइट डेटा और एडवांस्ड क्रांप मॉडलिंग का प्रयोग किया है। इससे फसल की वृद्धि अवस्था और स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप सुरक्षा मिलती है। बायर के मुताबिक इसमें प्लॉट-बेस्ड एग्रोनॉमिक पैरामीटर के हिसाब से ‘एश्योरेंस बॉनिफिट’ मिलता है, जिसे किसान नजदीकी बायर चैनल पार्टनर के पास जाकर तुरंत रिडीम कर सकते हैं। इससे उन्हें गुणवत्तापूर्ण बीज और फसल सुरक्षा के लिए आवश्यक उत्पाद तुरंत मिल जाते हैं, जिससे फसल चक्र के दौरान आने वाली चुनौतियों से बचाव करना संभव होता है। यह पारंपरिक बीमा में पारदर्शिता की कमी को भी दूर करता है। स्ट्रीट, डेटा-आधारित ट्रिगर्स और स्पष्ट संचार के माध्यम से किसानों को यह पता होता है कि कब वे संरक्षित हैं और कब लाभ सक्रिय है। इससे सीजन के दौरान चिंता कम होती है।

डीएफएस सचिव ने अस्पतालों तथा बीमा कंपनियों के बीच अधिक सहयोग पर जोर दिया

नई दिल्ली। वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) सचिव ने लागत नियंत्रण और मानकीकरण के माध्यम से अस्पतालों तथा बीमा कंपनियों के बीच अधिक सहयोग पर जोर दिया। सचिव ने बीमा कंपनियों से आग्रह किया कि वे पॉलिसीधारकों को विशेष रूप से अस्पताल में भर्ती होने और दवाों के निपटार के दौरान, उच्चतम स्तर की सेवाएं तथा समयबद्ध सुविधा प्रदान करें। वित्त मंत्रालय के मुताबिक देश में महंगी होती चिकित्सा और बढ़ती प्रीमियम लागत की कमी को भी दूर करता है। 13 नवंबर को वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) के सचिव एम नागराजू की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। बैठक में सचिव ने सलाह दी कि स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक किफायती व सुलभ बनाने के लिए बीमा कंपनियों और अस्पताल राष्ट्रीय स्वास्थ्य दावा एक्सचेंज में शामिल होने की प्रक्रिया तेज करें। उपचार प्रोटोकॉल को मानकीकृत करें, सामान्य पैनेल मार्गदर्श अपनाएं तथा कैशलेस दावा प्रसंस्करण को अधिक सरल एवं निर्बाध बनाएं।

बॉल कॉर्पोरेशन अपने आंध्र प्रदेश कारखाने में 60 मिलियन डॉलर का करेगी निवेश

नई दिल्ली। सस्टेनेबल एल्युमीनियम पैकेजिंग के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी बॉल कॉर्पोरेशन ने भारत में रणनीतिक निवेश करने की घोषणा की है। बॉल कॉर्पोरेशन ने महाराष्ट्र में मुंबई के नजदीक स्थित तालोजा केन मैयूफैक्चरिंग कारखाने में 2024 में 55 मिलियन डॉलर का निवेश किया था। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए कंपनी अब आंध्र प्रदेश में अपने श्री सिटी मैयूफैक्चरिंग कारखाने में करीब 60 मिलियन डॉलर का निवेश करने जा रही है। बॉल कॉर्पोरेशन ने एक बयान में कहा कि यह कदम एशिया के सबसे तेजी से बढ़ते उपभोक्ता बाजारों में से एक में अपनी आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने और ग्राहकों की बढ़ती मांग को पूरा करने की कंपनी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कंपनी की इस घोषणा से एशिया के सबसे तेजी से बढ़ते उपभोक्ता बाजार में अपनी सप्लाई चेन को मजबूत करने और ग्राहकों की बढ़ती मांग को पूरा करने की कंपनी की प्रतिबद्धता को मजबूती मिली है। बॉल बेवेरेज पैकेजिंग एम्प्लेय एंड एशिया के प्रेसिडेंट मैंडी ग्ल्यू ने एक बयान में कहा कि भारत हमारी वैश्विक रणनीति का प्रमुख केंद्र है। यह निवेश उच्च विकास वाले बाजारों में परिचालन विस्तार और लंबी अवधि में प्रतिस्पर्धा में आगे बने रहने की हमारी केंद्रित रणनीति (फोकस्ड एप्रोच) को दर्शाता है। तालोजा और श्री सिटी में अपने विस्तार की दिशा में आगे बढ़ते हुए हम भारतीय बाजार में विकास के लिए निवेश की अन्य संभावनाओं पर भी काम कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा ब्रांड एवं उपभोक्ता एल्युमीनियम पैकेजिंग का विकल्प चुन रहे हैं।

भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला शुरू, 19 नवंबर से जा सकेंगे आम लोग

नई दिल्ली। दिल्ली के भारत मंडपम में 44वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला शुरू हो गया। मेले उद्घाटन केंद्रीय वाणिज्य एवं व्यापार राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने किया। हर साल 14 नवंबर से शुरू होने वाले इस मेले में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ विदेशों से भी व्यापारी आये हुए हैं। पहले पांच दिन व्यापारियों और थोक खरीददारों के लिए है जबकि आम लोग 19 से 27 नवंबर तक जा सकेंगे। पहले पांच दिन मेले में प्रवेश के लिए वयस्कों के लिए टिकट की दर 150 रुपये और बच्चों के लिए 60 रुपये रखी गयी है। वहीं, 19 नवंबर से 27 नवंबर तक वयस्कों के लिए टिकट 80 रुपये और बच्चों के लिए 40 रुपये का होगा। वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांगज के लिए टिकट की आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोग वैध पहचान पत्र के साथ नि:शुल्क प्रवेश कर सकते हैं। मेले का थीम है - ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत ’। इसमें 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और 12 देशों के कारोबारी और कंपनियाँ हिस्सा ले रही हैं।

सीबीआईसी के अध्यक्ष ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में ‘जीएसटी एवं सीमा शुल्क मंडप’ का उद्घाटन किया

एजेंसी नई दिल्ली। केंद्रीय अग्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के अध्यक्ष संजय कुमार अग्रवाल ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में 44वें भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला में जीएसटी एवं सीमा शुल्क पैवेलियन का उद्घाटन किया। इस पैवेलियन का विषय नेक्स्ट-जेन जीएसटी: सरल कर, समृद्ध राष्ट्र है। मेले की पूरी अवधि में यह पैवेलियन खुला रहेगा, जिससे आगंतुकों को अप्रत्यक्ष कराधान के उपरते परिदृश्य का अनुभव करने का एक अनूठा अवसर प्राप्त होगा। इस अवसर पर संजय कुमार अग्रवाल ने जीएसटी एवं सीमा शुल्क प्रशासन की डिजिटलीकरण, पारदर्शिता एवं ‘इंज ऑफ डूंग ग्विजनेस’ की

दिशा में परिवर्तनकारी यात्रा पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि नेक्स्ट-जेन जीएसटी सुधार संचरनात्मक सुधार, दूरों का तर्कसंगत पुरीक्षण एवं इंज ऑफ लिविंग तीन मुख्य स्तंभों पर आधारित हैं। इसका उद्देश्य आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं को जनता के लिए ज्यादा वहनीय बनाना है, जबकि कर प्रक्रियाओं को सरलताओं एवं व्यवसायों दोनों के लिए सरल, तेज एवं आसानी सुलभ बनाना है।उन्होंने आगे कहा कि इस मंडप को जीएसटी बचत उत्सव के अंतर्गत इन सुधारों को प्रभावी रूप से फैलाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे आगंतुकों को लाभों को समझने एवं नई पहलों के माध्यम से प्रदान की जाने वाली अधिकतम बचत एवं राहत का लाभ

इंडिगो, अकासा एयर 25 दिसंबर से नवी मुंबई हवाई अड्डे से उड़ानें शुरू करेंगी

एजेंसी मुंबई। बजट एयरलाइन इंडिगो और अकासा एयर 25 दिसंबर से नवनिर्मित नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से अपने उड़ानों का संचालन शुरू करेगी। एयरलाइन ने शनिवार को एक बयान में कहा कि वह 25 दिसंबर से नवनिर्मित नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से 10 शहरों के लिए घरेलू हवाई सेवाओं के साथ उड़ान संचालन शुरू करेगी।

इसके तहत घरेलू हवाई सेवाओं के जरिये 10 शहरों को जोड़ा जाएगा। वहीं, अकासा एयर ने कहा कि वह 25 दिसंबर से चरणबद्ध तरीके से नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से परिचालन शुरू करेगी। इंडिगो ने कहा कि वह 25 दिसंबर से भविष्य के लिए तैयार एयरपोर्ट को दिल्ली, बंगलुरु,



और मंगलुरु सहित भारत के 10 शहरों से जोड़ेगा। कंपनी ने कहा कि वह मुंबई महानगर क्षेत्र के दूसरे हवाई अड्डे से

अपने परिचालन का विस्तार करने की योजना बना रही है। इसमें समय के

फ्लिपकार्ट ने 1,000 रुपये से कम मूल्य के उत्पादों के लिए लॉन्च किया जीरो कमीशन मॉडल

एजेंसी नई दिल्ली। ई-कॉमर्स क्षेत्र की प्रमुख कंपनी फ्लिपकार्ट ने 1,000 रुपये से कम कीमत वाले सभी उत्पादों के लिए शून्य कमीशन मॉडल पेश किया है। इसके साथ ही कंपनी ने अपने सेलर रेट कार्ड में महत्वपूर्ण

बदलाव किया है। यह नया मॉडल फ्लिपकार्ट के किफायती दामों पर सामान उपलब्ध कराने वाले मंत्र शॉप्सी पर भी लागू किया गया है। अब शॉप्सी पर सभी उत्पादों पर, चाहे कीमत कुछ भी हो, कमीशन नहीं लगेगा। इस नई व्यवस्था के तहत 1,000 रुपये से कम मूल्य वाले उत्पाद सूचीबद्ध करने वाले सभी योग्य विक्रेताओं से कमीशन शुल्क

नहीं लिया जाएगा। कंपनी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एस. चौधरी ने कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में लगभग 30 फीसदी योगदान देता है और फ्लिपकार्ट का उद्देश्य इस क्षेत्र का समर्थन करना, बाधाओं को दूर करना और

लेना आसान होगा। इन बदलावों से सभी को बराबरी का मौका देने, परिचालन में पारदर्शिता लाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, एमएसएमई को सशक्त करने और भारत के समावेशी डिजिटल रिटेल ट्रांसफॉर्मेशन को गति देने की फ्लिपकार्ट की प्रतिबद्धता को मजबूती मिली है।

मामूली बढ़त के साथ हरे निशान बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 84 अंक उछला

एजेंसी नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव नतीजे और विदेशों से मिले नकारात्मक संकेतों के बीच हफ्ते के अंतिम कारोबारी दिन शेयर बाजार मामूली बढ़त के साथ हरे निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 84 अंक चढ़ा,

जबकि एनएसई निफ्टी में 31 अंक की तेजी रही। शेयर बाजार दिनभर के उतार-चढ़ाव भरे कारोबार के बीच शुरुआती गिरावट से उबर कर मामूली बढ़त के साथ बंद होने में कामयाब रहा। बीएचबे सर्टीफ़ेड एक्सचेंज (बीएसई) का सेंसेक्स 84.11 अंक यानी 0.100 फीसदी उछल कर 84,562.78 पर बंद हुआ। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी भी 30.90 अंक यानी 0.12 फीसदी बढ़ कर 25,910.05 के स्तर पर बंद हुआ। इससे पहले कारोबार की शुरुआत में 30 शहरों वाला बीएसई का सेंसेक्स



का निफ्टी 138.35 अंक यानी 0.53 फीसदी फिसल कर 25,740.80 पर खुला था। हालांकि, दोनों प्रमुख सूचकांकों ने बाद में

सुधार दर्ज किया और लगातार चौथे दिन बढ़त के साथ शेयर बाजार बंद हुआ। कारोबार के दौरान निवेशकों ने



निचले स्तर पर प्रमुख कंपनियों के शेयरों में खरीदारी की, जिससे बाजार बढ़त में रहा। सेंसेक्स में शामिल कंपनियों में इटर्नल, भारत

इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रेट, एक्सिस बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बजाज फाइनेंस, सन फार्मास्यूटिकल्स, एशियन पेट्रोल, अदाणी पोर्ट्स, हिंदुस्तान यूनिटीवर, रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईटीसी, पाराग्रिड और बजाज फिनसर्व के शेयरों बढ़ कर बंद हुए। वहीं, इफोसिस, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स, टाटा स्टील, आईसीआईसीआई बैंक, टेक महिंद्रा, टाइटन, अल्ट्राटेक सोमेट, महारित सुजुकी इंडिया और लार्सन एंड टुब्रो के शेयर नुकसान में बंद हुए।

एक दिन पहले उतार-चढ़ाव के कारोबार के बीच सेंसेक्स 12.16 अंक यानी 0.014 फीसदी की मामूली बढ़त के साथ 84,478.67 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं, एनएसई का निफ्टी 3.35 अंक यानी 0.013 फीसदी बढ़ कर 25,879.15 के स्तर पर बंद होने में कामयाब रहा था।

देश का विदेशी मुद्रा भंडार 2.7 अरब डॉलर घटकर 687 अरब डॉलर पर

एजेंसी मुंबई। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर झटका लगने वाली खबर है। पिछले कुछ हफ्तों से विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट का सिलसिला जारी है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 7 नवंबर को समाप्त हफ्ते में 2.69 अरब डॉलर घटकर 687.03 अरब डॉलर रहा।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने जारी आंकड़ों में बताया कि 7 नवंबर को समाप्त हफ्ते में देश का विदेशी मुद्रा भंडार घटकर 687.03 अरब डॉलर रहा है। इससे पिछले सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 5.62 अरब डॉलर घटकर 689.73 अरब डॉलर रह गया था। आंकड़ों के अनुसार 7 नवंबर को समाप्त हफ्ते में विदेशी मुद्रा भंडार का प्रमुख घटक

विदेशी मुद्रा आस्तियां 2.45 अरब डॉलर घटकर 562.14 अरब डॉलर

आहरण अधिकार (एसडीआर) भी 5.1 करोड़ डॉलर घटकर 18.59



रह गई। आरबीआई ने बताया कि इस दौरान स्वर्ण भंडार का मूल्य 19.5 करोड़ डॉलर घटकर 101.53 अरब डॉलर रहा। इसके अलावा विशेष

अरब डॉलर रह गया। आंकड़ों के अनुसार इस अवधि में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) में भारत का आरक्षित भंडार 4.77 अरब डॉलर पर अपरिवर्तित बना रहा।

गया है। इसके आयोजन में इस साल के भागीदार राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और बिहार हैं। इस बार झारखंड ‘फोकस स्टेट’ है। इसके अलावा राज्य दिवस समारोह, सम्मेलन, कार्यशालाएं, सेमिनार और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रतिदिन आयोजित किए जाएंगे। आईआईटीएफ-2025 14-18 नवंबर तक है, जबकि सामान्य दिनों के लिए भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला 19-27 नवंबर तक चलेगा, जिसका समय: सुबह 10:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक (आम जनता के लिए) है।

क्या है। इसके आयोजन में इस साल के भागीदार राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान,

महाराष्ट्र और बिहार हैं। इस बार झारखंड

‘फोकस स्टेट’ है। इसके अलावा राज्य

दिवस समारोह, सम्मेलन, कार्यशालाएं,

सेमिनार और सांस्कृतिक कार्यक्रम

प्रतिदिन आयोजित किए जाएंगे। आईआईटीएफ-

2025 14-18 नवंबर तक है, जबकि सामान्य दिनों के लिए

भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला 19-

27 नवंबर तक चलेगा, जिसका समय:

सुबह 10:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक

(आम जनता के लिए) है।

क्या है। इसके आयोजन में इस साल के भागीदार राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान,

महाराष्ट्र और बिहार हैं। इस बार झारखंड

‘फोकस स्टेट’ है। इसके अलावा राज्य

दिवस समारोह, सम्मेलन, कार्यशालाएं,

सेमिनार और सांस्कृतिक कार्यक्रम

प्रतिदिन आयोजित किए जाएंगे। आईआईटीएफ-

2025 14-18 नवंबर तक है, जबकि सामान्य दिनों के लिए

भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला 19-

27 नवंबर तक चलेगा, जिसका समय:

सुबह 10:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक

(आम जनता के लिए) है।

क्या है। इसके आयोजन में इस साल के भागीदार राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान,

महाराष्ट्र और बिहार हैं। इस बार झारखंड

‘फोकस स्टेट’ है। इसके अलावा राज्य

दिवस समारोह, सम्मेलन, कार्यशालाएं,

सेमिनार और सांस्कृतिक कार्यक्रम

प्रतिदिन आयोजित किए जाएंगे। आईआईटीएफ-

2025 14-18 नवंबर तक है, जबकि सामान्य दिनों के लिए

भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला 19-

27 नवंबर तक चलेगा, जिसका समय:

सुबह 10:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक

(आम जनता के लिए) है।

क्या है। इसके आयोजन में इस साल के भागीदार राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान,

महाराष्ट्र और बिहार हैं। इस बार झारखंड

‘फोकस स्टेट’ है। इसके अलावा राज्य

दिवस समारोह, सम्मेलन, कार्यशालाएं,

सेमिनार और सांस्कृतिक कार्यक्रम

प्रतिदिन आयोजित किए जाएंगे। आईआईटीएफ-

2025 14-18 नवंबर तक है, जबकि सामान्य दिनों के लिए

भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला 19-

27 नवंबर तक चलेगा, जिसका समय:

सुबह 10:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक

(आम जनता के लिए) है।

क्या है। इसके आयोजन में इस साल के भागीदार राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान,

महाराष्ट्र और बिहार हैं। इस बार झारखंड

‘फोकस स्टेट’ है। इसके अलावा राज्य

दिवस समारोह, सम्मेलन, कार्यशालाएं,

सेमिनार और सांस्कृतिक कार्यक्रम

प्रतिदिन आयोजित किए जाएंगे। आईआईटीएफ-

2025 14-18 नवंबर तक है, जबकि सामान्य दिनों के लिए

भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला 19-

27 नवंबर तक चलेगा, जिसका समय:

सुबह 10:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक

(आम जनता के लिए) है।

क्या है। इसके आयोजन में इस साल के भागीदार राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान,

महाराष्ट्र और बिहार हैं। इस बार झारखंड

‘फोकस स्टेट’ है। इसके अलावा राज्य

दिवस समारोह, सम्मेलन, कार्यशालाएं,

सेमिनार और सांस्कृतिक कार्यक्रम

प्रतिदिन आयोजित किए जाएंगे। आईआईटीएफ-

2025 14-18 नवंबर तक है, जबकि सामान्य दिनों के लिए

भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला 19-

27 नवंबर तक चलेगा, जिसका समय:

सुबह 10:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक

(आम जनता के लिए) है।

क्या है। इसके आयोजन में इस साल के भागीदार राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान,

महाराष्ट्र और बिहार हैं। इस बार झारखंड

‘फोकस स्टेट’ है। इसके अलावा राज्य

दिवस समारोह, सम्मेलन, कार्यशालाएं,

सेमिनार और सांस्कृतिक कार्यक्रम

प्रतिदिन आयोजित किए जाएंगे। आईआईटीएफ-

2025 14-18 नवंबर तक है, जबकि सामान्य दिनों के लिए

भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला 19-

27 नवंबर तक चलेगा, जिसका समय:

सुबह 10:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक

(आम जनता के लिए) है।

क्या है। इसके आयोजन में इस साल के भागीदार राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान,

महाराष्ट्र और बिहार हैं। इस बार झारखंड

‘फोकस स्टेट’ है। इसके अलावा राज्य

दिवस समारोह, सम्मेलन, कार्यशालाएं,

सेमिनार और सांस्कृतिक कार्यक्रम

प्रतिदिन आयोजित किए जाएंगे। आईआईटीएफ-

2025 14-18 नवंबर तक है, जबकि सामान्य दिनों के लिए

भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला 19-

27 नवंबर तक चलेगा, जिसका समय:

सुबह 10:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक

(आम जनता के लिए) है।

क्या है। इसके आयोजन में इस साल के भागीदार राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान,

महाराष्ट्र और बिहार हैं। इस बार झारखंड

‘फोकस स्टेट’ है। इसके अलावा राज्य

दिवस समारोह, सम्मेलन, कार्यशालाएं,

सेमिनार और सांस्कृतिक कार्यक्रम

प्रतिदिन आयोजित किए जाएंगे। आईआईटीएफ-

2025 14-18 नवंबर तक है, जबकि सामान्य दिनों के लिए

भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला 19-

27 नवंबर तक चलेगा, जिसका समय:

सुबह 10:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक

(आम जनता के लिए) है।

क्या है। इसके आयोजन में इस साल के भागीदार राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान,

महाराष्ट्र और बिहार हैं। इस बार झारखंड

‘फोकस स्टेट’ है। इसके अलावा राज्य

दिवस समारोह, सम्मेलन, कार्यशालाएं,

सेमिनार और सांस्कृतिक कार्यक्रम

प्रतिदिन आयोजित किए जाएंगे। आईआईटीएफ-

2025 14-18 नवंबर तक है, जबकि सामान्य दिनों के लिए

भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला 19-

27 नवंबर तक चलेगा, जिसका समय:

सुबह 10:00 बजे से शाम

यूके ने ग्लोबल हेल्थ फंड में की 15 फीसदी कटौती, स्वास्थ्य संगठन बोले-अफ्रीकी देशों पर पड़ेगा असर

एजेंसी यूके। यूके ने 'ग्लोबल हेल्थ फंड' में 15 फीसदी कटौती करने के फैसले ने दुनिया के कई प्रमुख स्वास्थ्य संगठनों को चिंता में डाल दिया है। 'ग्लोबल फंड', 'यूएनएड्स', 'डब्ल्यूएचओ' (विश्व स्वास्थ्य संगठन), 'एमएसएफ' और 'मलेरिया नो मोर यूके' जैसे संगठनों ने साफ कहा है कि इस कदम का सबसे ज्यादा नुकसान अफ्रीकी देशों को होगा, जहां पहले से ही संसाधन सीमित हैं और बड़ी आबादी एचआईवी, टीबी और मलेरिया जैसी बीमारियों से जूझ रही है। यूके पहले ग्लोबल फंड में लगभग 1 अरब पाउंड स्टर्लिंग का योगदान करता था, लेकिन अब यह घटकर 850 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग रह गया है। ग्लोबल फंड ने कहा कि यह कटौती अफ्रीका के लिए 'सीधा झटका' है, क्योंकि इन बीमारियों से लड़ने के लिए सबसे ज्यादा निर्भरता इसी फंड पर है। यूएनएड्स ने चेतावनी दी कि इससे कई देशों में एचआईवी रोकथाम कार्यक्रम धीमे पड़ जाएंगे और कई लोग समय पर दवा न मिलने की वजह से खतरे में आ सकते हैं। डब्ल्यूएचओ ने कहा कि अफ्रीका जैसे महाद्वीप, जहां स्वास्थ्य ढांचा पहले ही कमजोर है, वहां यह कटौती 'जिंदगियों की कीमत' पर पड़ेगी। अक्टूबर में प्रकाशित एक शोध के अनुसार ग्लोबल फंड में 20 फीसदी की कटौती से 2040 तक अकेले मलेरिया से 3,30,000 अतिरिक्त मौतें होंगी। यह कोष मलेरिया के लिए 59 फीसदी अंतर्राष्ट्रीय फंड प्रदान करता है।

जमैका में मेलिसा तुफान से हुई तबाही के बाद भारत ने बढ़ाया मदद का हाथ, नेजी राहत सामग्री

किंग्स्टन । जमैका में मेलिसा तुफान की वजह से हुई भारी तबाही से उबरने के लिए भारत ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया। इसके साथ ही किंग्स्टन में भारतीय समुदाय के सदस्यों ने कैरेबियाई राष्ट्र के सेंट एलिजाबेथ पैरिश में प्रभावित समुदायों का दौरा किया। जमैका के साथ भारत ने एकजुटता की पुष्टि की। किंग्स्टन स्थित भारतीय उच्चायोग ने तत्काल राहत के लिए भारतीय समुदाय की ओर से किए गए प्रयासों की सराहना की। भारतीय समुदाय ने 32 लाख डॉलर से अधिक की राशि जुटाई और सेंट एलिजाबेथ, वेस्टमोरलैंड और ब्लैक रिवर के प्रभावित परिवारों के लिए 550 केयर पैकेज, स्टोव, कपड़े, बैग और स्वच्छता किट आदि तैयार किए और वितरित किए। किंग्स्टन स्थित भारतीय उच्चायोग ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, "भारत राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण प्रयासों में जमैका के साथ एकजुटता में खड़ा है। भारतीय समुदाय द्वारा दिखाई गई करुणा और एकजुटता 'वसुधैव कुटुम्बकम्', यानी दुनिया एक परिवार है, के भारतीय दर्शन को दर्शाती है।" मेलिसा तुफान से हुई तबाही के बाद राहत के लिए मदद कर रही भारतीय समुदाय की टीम में जमैका में भारतीय उच्चायुक्त सयंक जोशी और जमैका के कृषि, मत्स्य पालन एवं खनन मंत्री फ्लॉयड ग्रीन भी शामिल हुए। इसका नेतृत्व गुल मनसुखानी ने किया।

तालिबान के खिलाफ प्रतिबंधों को लेकर भारत ने पाकिस्तान की लगाई वलास, सुरक्षा परिषद समिति की अध्यक्षता को लेकर घेरा

संयुक्त राष्ट्र । भारत ने तालिबान के खिलाफ प्रतिबंधों पर सुरक्षा परिषद की समिति का नेतृत्व करने और आतंकवाद विरोधी पैनाल की सह-अध्यक्षता करने वाले पाकिस्तान की जमकर आलोचना की। पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी. हरीश ने परिषद की कार्यप्रणाली पर हुई बहस में कहा कि परिषद के सदस्यों को निहित स्वार्थ वाली समितियों की अध्यक्षता करने से रोका जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि परिषद में हिंतां के टकराव के लिए कोई जगह नहीं हो सकती है। बता दें, पाकिस्तान परिषद का दो साल का निर्वाचित सदस्य है। पी. हरीश ने पाकिस्तान या तालिबान प्रतिबंध समितिया या आतंकवाद-रोधी समिति का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा। बता दें, समिति के गठन के प्रस्ताव के क्रमांक के आधार पर इसे 1988 समिति के रूप में जाना जाता है। इस समिति के पास तालिबान सदस्यों का यात्रा पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार है। इसी समिति की वजह से अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुताकी को भारत यात्रा में देरी हुई थी। गौरतलब है कि फिलहाल पाकिस्तान तालिबान के नेतृत्व वाले अफगानिस्तान के साथ संघर्ष में उलझा हुआ है। सीमा पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच झड़पें हुई हैं।

भारत, पैराग्वे ने पहली संयुक्त आयोग बैठक की, द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने पर हुई चर्चा

असुनसियन । भारत और पैराग्वे ने पैराग्वे की राजधानी असुनसियन में संयुक्त आयोग तंत्र (जेसीएम) की पहली बैठक आयोजित की। बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की। विदेश मंत्रालय (एम्बेई) ने बताया कि बैठक की सह-अध्यक्षता पराग्वे सरकार की ओर से वहां के उप विदेश मंत्री, राजदूत विक्टर वर्दुन और भारत की ओर से विदेश मंत्रालय के सचिव (पूर्व) पेरियासामी कुमारन ने की। विदेश मंत्रालय के अनुसार, दोनों पक्षों ने पराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना पलासियोस की हालिया भारत राजकीय यात्रा से प्रेरित द्विपक्षीय संबंधों में आइ नई गतिशीलता पर प्रकाश डाला। राष्ट्रपति पेना का ये दौरा राजनीतिक संवाद को मजबूत करने और साझा हितां के विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को गहरा करने में एक महत्वपूर्ण मील का पथर साबित हुआ।

ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में पहला बड़ा रक्षा सौदा, ताइवान के लिए 33 करोड़ डालर का हथियार सौदा

एजेंसी वाशिंगटन/ताइपे। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने ताइवान के लिए 33 करोड़ डालर के महत्वपूर्ण हथियार सौदे को मंजूरी दे दी। यह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में पहला बड़ा रक्षा सौदा है। यह सौदा एफ-16 लड़ाकू जेट के लिए स्पेयर पार्ट्स, मरम्मत और सहायक उपकरणों से जुड़ा है, जो ताइवान की वायु रक्षा क्षमता को मजबूत करेगा। अमेरिकी विदेश विभाग ने यह जानकारी दी। डिफेंस सिस्तेमोरिटी ऑफ़ोपरेशन एजेंसी (डीएससीए) के मुताबिक यह सौदा ताइवान की 'रक्षा स्वतंत्रता' को बढ़ावा देगा। यह अनुमोदन ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनिपिंग की



व्यापार सौदे पर चर्चा हुई थी। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटीनी ब्लिंकेन के मुताबिक , 'यह सौदा

अक्टूबर 2025 में दक्षिण कोरिया में हुई मुलाकात के बाद आया है, जहां

चीन के यात्रा परामर्श पर जापान को कड़ा एतराज

एजेंसी टोक्यो। जापान ने चीन द्वारा अपने नागरिकों को जापान ना जाने संबंध में जारी परामर्श पर गहरी आपत्ति व्यक्त की है और चीन सरकार से इस पर पुनर्विचार करने को कहा है। जापान के मुख्य मंत्रिमंडल सचिव मिनोरु किहरा ने शनिवार को यहां कहा कि जापान ने चीन को संदेश भेजा है और 'उचित कदम उठाने' के लिए अनुरोध किया है।

किहरा ने कहा, 'हमने चीन को संदेश दिया है और उनसे उचित कार्रवाइयों के लिए दृढ़ता से अनुरोध किया है।' हालांकि उन्होंने इस मुद्दे पर विस्तार से टिप्पणी नहीं की, लेकिन जोर दिया कि दोनों देशों के बीच मतभेद हैं जिसके लिए संवाद बनाए रखना आवश्यक है। चीन ने यह परामर्श जापानी प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची के उस

हालिया बयान के बाद जारी किया है, जिसमे उन्होंने ताइवान पर



संभावित चीनी हमले को 'अस्तित्व के लिए खतरा' करार दिया था। ताकाइची ने पिछले सप्ताह कहा था कि ताइवान पर चीनी हमला 'जीवन-भर के खतरे' के समान होगा, जो जापान को सैन्य

प्रतिक्रिया के लिए प्रेरित कर सकता है। यह बयान जापान की पारंपरिक

रणनीतिक नीति से अलग है, जो अमेरिका के साथ जुड़ी है और ताइवान का सार्वजनिक उल्लेख से बचती रही है। चीन ताइवान को अपना अभिन्न अंग मानता है और द्वीप पर नियंत्रण के लिए बल प्रयोग

की संभावना से इनकार नहीं करता। ताइवान जापान के टट से मात्र 110 किलोमीटर दूर स्थित है, और ताइवानी सरकार चीन के दावों को खारिज करती रही है।

चीन के साथ रिश्तों में यह तनातनी इसलिए भी उपजी है क्योंकि जापान और अमेरिका ताइवान को समर्थन देते हैं। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना ​​है कि चीन का यात्रा परामर्शआर्थिक दबाव का माध्यम हो सकता है, क्योंकि जापान चीनी पर्यटकों पर निर्भर है। इस बीच जापान ने बातचीत की वकालत की है, लेकिन यदि चीन ने परामर्श वापस नहीं लिया तो द्विपक्षीय संबंध और खराब हो सकते हैं। हालांकि इस समय अमेरिका ने इस मुद्दे पर चुपची साधे रखी है, लेकिन यह तनाव एशियाई शांति को प्रभावित कर सकता है।

संदिग्ध गतिविधि के आरोप में 4 चीनी नागरिक गिरफ्तार, सभी व्यावसायिक वीज़ा पर आए

एजेंसी काठमांडू। व्यावसायिक वीजा पर नेपाल में रहते संदिग्ध गतिविधि संचालित करने के आरोप में चार चीनी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। अध्यागमन विभाग के प्रवक्ता टीकाराम ढकाल के अनुसार, एक महिला तथा तीन पुरुषों को गिरफ्तार किया गया। उन्हें काठमांडू के सोह्रबुट्टे क्षेत्र से नियंत्रण में लिया गया। यह स्थान बड़ी संख्या में चीनी नागरिकों के रहने के कारण 'चाइनीज हाउजिंग' नाम से भी जाना जाता है। गिरफ्तार चीनी नागरिकों के पास व्यावसायिक वीजा होने के बावजूद वे अपने व्यवसाय, कंपनी के नाम और उससे संबंधित किसी भी जानकारी का विवरण प्रस्तुत करने में असमर्थ पाए गए। प्रारंभिक जाँच में यह खुलासा हुआ है कि ये लोग आर्थिक रूप से कमजोर नेपाली युवतियों को नौकरी का प्रलोभन देकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म

टिकटक पर वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करते थे तथा टिकटक के माध्यम से अन्य चीनी नागरिकों से मित्रता कर विवाह करवाने की



कोशिश करते थे। अध्यागमन विभाग ने जानकारी दी कि कुछ युवतियों को चीन ले जाकर विवाह कराने के बहाने चीन भी भेजा गया था। इसके अतिरिक्त, घर किराए पर लेकर नेपाली युवतियों को रख जाता था और उन्हें विभिन्न देशों में ले जाया जाता था। नियंत्रण में लिए गए दो व्यक्तिों के बारे में यह भी पता चला है कि वे पिछले 10 वर्षों से नेपाल में पर्यटक, छत्र और व्यावसायिक वीजा पर रह रहे थे। वीजा जाँच के दौरान वे पासपोर्ट

और वीजा प्रस्तुत करने में विफल रहे तथा अध्यागमन और सुरक्षा अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार भी किया।

नेपाल के अध्यागमन कानून के अनुसार, विदेशियों के प्रवेश, उपस्थिति और प्रस्थान से संबंधित कागजातों की जाँच किसी भी समय और स्थान पर की जा सकती है तथा आवश्यकता पड़ने पर उन्हें हिरासत में लिया जा सकता है। अध्यागमन नियमावली के तहत विदेशी नागरिक जिस उद्देश्य के लिए वीजा प्राप्त करता है, उसके अतिरिक्त किसी अन्य गतिविधि में संलग्न नहीं हो सकता। अवैध रूप से नेपाल में रहने वाले ऐसे विदेशी नागरिकों पर जाँच उपरांत महानिदेशक द्वारा 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है तथा अवधि निर्धारित कर या बिना अवधि निर्धारित किए निष्कासन किया जा सकता है, जिससे उन्हें नेपाल में पुनः प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

नेपाल-चीन व्यापारिक नाकों पर कड़ाई: नेपाली व्यापारी परेशान

एजेंसी काठमांडू। नेपाल-चीन व्यापारिक नाकों पर चीन की कड़ाई के कारण नेपाली कटेनर समय पर नेपाल वापस ना आ पाने के कारण नेपाली व्यवसायी परेशान हैं। एक नाका बंद होने और चीन से भी आने वाले कटेनरों की संख्या में कमी आने की वजह से भी व्यापार प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहा है। नेपाल के व्यापारियों ने यह शिकायत की है। उल्लेखनीय है कि पाग जुलाई की बाढ़ के बाद से रसुवागढ़ी नाका पूर्ण रूप से बंद है, जबकि तातोपानी नाका को लंबे समय बाद संस्थान में लाया गया है। मुस्तांग चिंतल कोरला नाका खुलने के बावजूद, व्यापारी प्रमुख रूप से खाद्यान्न, वस्त्र, फलफूल सहित अन्य सामग्री रसुवागढ़ी व तातोपानी नाकों से ही आयात करते रहे हैं। कोरला नाका खुलने के साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) का

आयात भी शुरू हुआ है। व्यवसायियों का कहना है कि वर्तमान स्थिति में तातोपानी नाका से अपेक्षित संख्या में कटेनर नेपाल नहीं आ पा रहे। उनके अनुसार रसुवागढ़ी नाका बंद होने के चलते तातोपानी नाका पर अत्यधिक भीड़भाड़ हो रही है, जिससे और समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं। एक व्यापारी ने बताया कि पहले दो नाके चालू थे। एक दिन में एक नाके से 25-30 कटेनर आते थे, यानी दोनों से मिलकर 60-70 कटेनर आते थे। अब केवल एक नाका चलने के कारण भीड़ बढ़ी है और संभवतः इसी वजह से देरी हो रही है। आयात में देरी से परिवहन लागत और किराया भी बढ़ गया है। उधर, तातोपानी भंभरा कार्यालय के अधिकारी एवं सूचना अधिकारी रमेश बजुरा शहाने ने कहा कि हाल ही में चीन की ओर से बहुत कम संख्या में कटेनर नेपाल में प्रवेश कर रहे हैं।

पाकिस्तानी संसद ने सेना प्रमुख को दी अकूत शक्तियां

एजेंसी इस्लामाबाद। पाकिस्तान की संसद ने राष्ट्रपति के साथ-साथ वर्तमान सेना प्रमुख असीम मुनोरी को अजीवन वैधानिक प्रतिरक्षा प्रदान करने वाले एक व्यापक संवैधानिक संशोधन को मंजूरी दे दी। हालांकि एक बड़े वर्ग ने पाकिस्तानी संसद के इस कदम को लोकतांत्रिक संप्रभुता और न्यायिक स्वतंत्रता को नष्ट करने वाला आत्मघाती फैसला बताया है। राष्ट्रीय असेंबली में दो-तिहाई बहुमत से पारित 27वां संशोधन, जनरल असीम मुनोरी को 'फील्ड मार्शल' की भूमिका के तहत असीम सैन्य शक्तियां प्रदान करता है और एक संघीय संवैधानिक न्यायालय की स्थापना करता है। यह संशोधन पाकिस्तान के सैन्य और न्यायिक ढांचे में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा।विधेयक के तहत सेना प्रमुख को रक्षा बलों के प्रमुख 'चीफ आफ

डिफेंस फोर्सेज' का पद दिया जाएगा जो पांच सितारा रैंक का होगा। वह और अन्य शीर्ष सैन्य अधिकारियों अजीवन वैधानिक सुरक्षा हासिल करेंगे। उन्हें अब पदों से हटाने के लिए संसद के दो तिहाई बहुमत की आवश्यकता होगी।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार 27वें संशोधन के तहत, फ़ील्ड मार्शल, वायु सेना के मार्शल, या बड़े एडमिरल में पदोन्नत कोई भी अधिकारी अब जीवन भर के लिए एडमिरल में पदोन्नत होई की शर्तों पर रिटायर हो सकते हैं। इस तरह की सुरक्षा पहले केवल राष्ट्र के प्रमुख यानी राष्ट्रपति के लिए आरक्षित थी। इसके अलावा इसमें सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को सीमित करने का प्रावधान भी शामिल है, जिससे न्यायपालिका पर सैन्य प्रभाव बढ़ेगा। जनरल असेंबली

में इस विधेयक को मंगलवार को मंजूरी मिल गई थी जबकि सीनेट ने इसे ही स्वीकार किया।

हालांकि देश के कानूनविदों का कहना है कि यह संवैधानिक संशोधन अधिनायकवाद को बढ़ाएगा और देश में लोकतंत्र की जो भी छेटी सी झलक मौजूद थी, वह खत्म हो जाएगी। यह न केवल सेना की गतिविधियों पर लोकतांत्रिक अंकुश हटा देगा बल्कि यह सैन्य पदानुक्रम को भी पूरी तरह से परित्यक्त कर देगा जहां संयुक्त मुख्य प्रणाली के तहत सभी सेवा प्रमुखों को समान माना जाता था। विपक्षी दलों ने इसे तानाशाही की ओर कम बताते हुए संसद में हंगामा भी किया। हालांकि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेतृत्ववाली गठबंधन सरकार ने बहुमत का लाभ उठाते हुए इसे पारित करवाने में सफलता हासिल कर ली।

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने न्यूयॉर्क में की भारत-अमेरिका संबंधों की समीक्षा, भारतीय राजदूतों से हुई मुलाकात

एजेंसी वाशिंगटन । भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अमेरिका में भारतीय महावाणिज्य दूतों के एक सम्मेलन की अध्यक्षता की। सम्मेलन में भारत-अमेरिका द्विपक्षीय सहयोग और भारतीय प्रवासियों से जुड़ाव की समीक्षा के लिए देशभर के मिशनों के वरिष्ठ भारतीय राजनयिकों को बुलाया गया। शुक्रवार को न्यूयॉर्क में आयोजित इस बैठक में वाशिंगटन डीसी स्थित भारतीय दूतावास के अलावा न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, शिकागो, अटलांटा, ब्रुस्टन, बोस्टन, लॉस एंजिल्स और सिएटल स्थित वाणिज्य दूतावासों के वरिष्ठ राजनयिक शामिल हुए। बैठक को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लिखा, 'न्यूयॉर्क में महावाणिज्य दूतों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। हमारे द्विपक्षीय संबंधों और प्रवासी गतिविधियों के लिए समर्थन की समीक्षा की। भारत-अमेरिका साझेदारी को मजबूत करने के लिए हमारे दूतावास और वाणिज्य दूतावासों की प्रतिबद्धता और प्रयासों की सराहना करता हूं।' इस बैठक में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय राजदूत विनय वाम्ता भी शामिल हुए। इससे पहले भारत के विदेश मंत्री ने गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से फिर से पूर्वी एशिया की राजनीति के केंद्र में आ गया है।

हालांकि संवाद के दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं। अंतरराष्ट्रीय समुदाय, विशेष रूप से अमेरिका और आसियान देशों, ने दोनों पक्षों से संयम बताने की अपील की है। लेकिन स्पष्ट है कि ताइवान मुद्दा अब फ़िर से पूर्वी एशिया की राजनीति के केंद्र में आ गया है।

चीन-जापान में बढ़ती तनातनी: पीएम ताकाइची की ताइवान टिप्पणी पर गहराया विवाद, बीजिंग ने जारी की यात्रा-चेतावनी

एजेंसी बीजिंग/टोक्यो। पूर्वी एशिया में सामरिक तनाव ने एक नया मोड़ लिया है। चीन ने जापानी प्रधानमंत्री साने ताकाइची की हालिया टिप्पणी के बाद अपने नागरिकों को जापान की यात्रा से बचने की सलाह जारी कर दी है। ताकाइची ने कहा था कि ताइवान पर किसी संभावित संघर्ष की स्थिति में जापान 'सैनिकों की तैनाती पर विचार कर सकता है।' बीजिंग ने इस बयान को 'उकसावे वाला' और 'अत्यंत आपत्तिजनक' बताया है। इसके बाद दोनों देशों के

बीच कूटनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है, और क्षेत्र में अई अस्थिरता की आशंका बढ़ गई है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि जापानी पीएम की यह टिप्पणी उचित नहीं है। बीजिंग ने दावा किया कि यह बयान एशिया-प्रशांत क्षेत्र की शांति और स्थिरता को नुकसान पहुंचाता है। इसके बाद चीन ने अपने नागरिकों से कहा कि वे जापान की यात्रा योजना पर पुनर्विचार करें, भीड़भाड़ वाले स्थानों से बचें, और सुरक्षा को प्राथमिकता दें। यह सलाह ऐसे वक्त आई है जब दोनों देशों के बीच

व्यापार, तकनीक, और समुद्री सुरक्षा को लेकर पहले से ही कई मतभेद मौजूद हैं। दरअसल, 7 नवंबर को पीएम ताकाइची ने संसद में जो कहा उस पर ही क्रिया और प्रतिक्रिया का दौरा जारी है। जापानी पीएम के बयान को लेकर ओसाका में चीनी महावाणिज्य दूत जू जियान ने एक 'अनुचित' और 'अब हटा दी गई' ऑनलाइन पोस्ट की थी। इसके बाद चीन के राजदूत को तहब किया गया था। सोशल मीडिया पर अब हटाए जा चुके बयान में, जू ने 'उस गंदी गर्दन को (काटने)' के बारे में पोस्ट

किया था, जो स्पष्ट रूप से ताकाइची के संदर्भ में था। जापान की सत्तारूढ़ पार्टी ने तब से एक प्रस्ताव पारित कर राजदूत को अवांछित व्यक्ति घोषित करने का आह्वान किया।

वहीं, बीजिंग इस बात पर बल देता आया है कि ताइवान उसका हिस्सा है और उसने नियंत्रण हासिल करने के लिए बल प्रयोग से इनकार नहीं किया है। चीन और जापान प्रमुख व्यापारिक साझेदार हैं, लेकिन क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता और सैन्य खर्च को लेकर ऐतिहासिक अविश्वास और टकराव अक्सर इन संबंधों की परीक्षा

लेते हैं। एक रूढ़िवादी और चीन समर्थक ताकाइची ने पिछले महीने पदभार ग्रहण करने के बाद से अपनी बयानबाजी में नरमी बरती है, लेकिन पिछले हफ्ते उनकी टिप्पणी ने दोनों देशों के बीच मतभेद पैदा कर दिए हैं। जापान ने इस चेतावनी को 'अनुचित और राजनीतिक रूप से प्रेरित' बताया है। टोक्यो का कहना है कि पीएम ताकाइची का बयान सिर्फ जापान की रक्षा रणनीति को समझाने के लिए था, जिसकी पृष्ठभूमि ताइवान स्ट्रेट में चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियां हैं। जापान यह भी बार-

बार कहता रहा है कि उसके लिए ताइवान स्ट्रेट की स्थिरता अत्यंत आवश्यक है क्योंकि तब से उसकी व्यापारिक समुद्री लाइनें गुजरती हैं। विवाद की तोड़ता इस बात से भी बढ़ी है कि जापान हाल के वर्षों में अमेरिका के साथ अपने सुरक्षा गठजोड़ को मजबूत कर रहा है, जबकि चीन इसे क्षेत्रीय 'घेराबंदी' के रूप में देखता है। इस कूटनीतिक टकराव के बीच दोनों देशों ने अपने दूतावासों के माध्यम से आपसी आरोप-प्रत्यारोप भी तेज कर दिए हैं। चीन का कहना

